सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 170, नई दिल्ली | शनिवार, 02 सितम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

शतरंज का एक नियम बहुत ही उमदा है, चाल कोई भी चलो पर अपनों को नहीं मार सकते।

दिल्ली में तीन दिन नो एंट्री: ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी, भारी वाहनों के रूट डायवर्ट

संजय बाटला, संपादक

भारी वाहनों को पचगांव से केएमपी के रास्ते आगे भेजा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसों को इफ्को चौक से डायवर्ट करते हुए एमजी रोड आया नगर के रास्ते दिल्ली भेजा जाएगा।

नई दिल्ली। दिल्ली में होने वाली जी-20 की बैठक को लेकर साइबर सिटी में तैयारियां जोरों पर हैं। बैठक के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 7 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक दिल्ली में बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। यह पाबंदी धौला कुआं रूट पर होगी।

इस रूट पर न केवल भारी वाहन, बल्कि बसों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। इसके अलावा इस रूट पर निजी वाहनों से जाने वालों को भी उस वक्त रोका जाएगा जब विदेशी डेलीगेट्स की मूवमेंट होगी।

डीसीपी ट्रैफिक विरेंद्र विज ने बताया कि दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम 9 सितंबर को है, जबकि 8 सितंबर से डेलीगेट्स का दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। वहीं कुछ डेलीगेट्स होटल लीला व ट्राइडेंट होटल में ठहरेंगे। ऐसे में यहां भी वाहनों की मूवमेंट रोकी जाएगी, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशान होना पड़ सकता है। वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है।

भारी वाहनों को पचगांव से केएमपी के रास्ते आगे भेजा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसों को इफ्को चौक से डायवर्ट करते हुए एमजी रोड आया नगर के रास्ते दिल्ली भेजा जाएगा। वहीं, गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी और अन्य कंपनियों को कहा गया है कि शनिवार व रविवार को उनकी कंपनी का अवकाश होता है। ऐसे में वह शुक्रवार 8 सितंबर को भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने दिया जाए, ताकि वाहनों की आवाजाही कम हो जाए और विदेशी मेहमानों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके।

तावडू के होटल में रुकेंगे विदेशी

डीसीपी ट्रैफिक का कहना है कि रविवार से ही विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। तावडू स्थित आईटीसी ग्रांड होटल में विदेशी रुकेंगे। ऐसे में दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते तावडू तक उनकी आवाजाही रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

तैयारियों को लेकर होगी मॉकड्रिल

डीसीपी ने बताया कि जी-20 की तैयारियों को लेकर जल्द ही मॉकड्रिल की जाएगी और वाहनों का रूट भी डायवर्ट किया जाएगा। हाईवे पर वाहनों के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में इन्हें तुरंत हटाने के लिए क्रेन का भी इंतजाम किया जाएगा। रूट डायवर्जन और दिल्ली में नो एंट्री के मद्देनजर शहर की अंदरूनी सडक़ों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए 100 अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।

एयरपोर्ट जाने वाले जल्दी घर से निकलें

डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि इस दौरान हवाई अड्डे जाने वालों को सबसे अधिक परेशानी होगी। घर से निकलने से पहले वह समय लेकर चलें। दिल्ली किसी को जाना है तो मेट्रो का प्रयोग करें। कार से अगर जा रहे हैं तो महरौली रोड का इस्तेमाल करें।

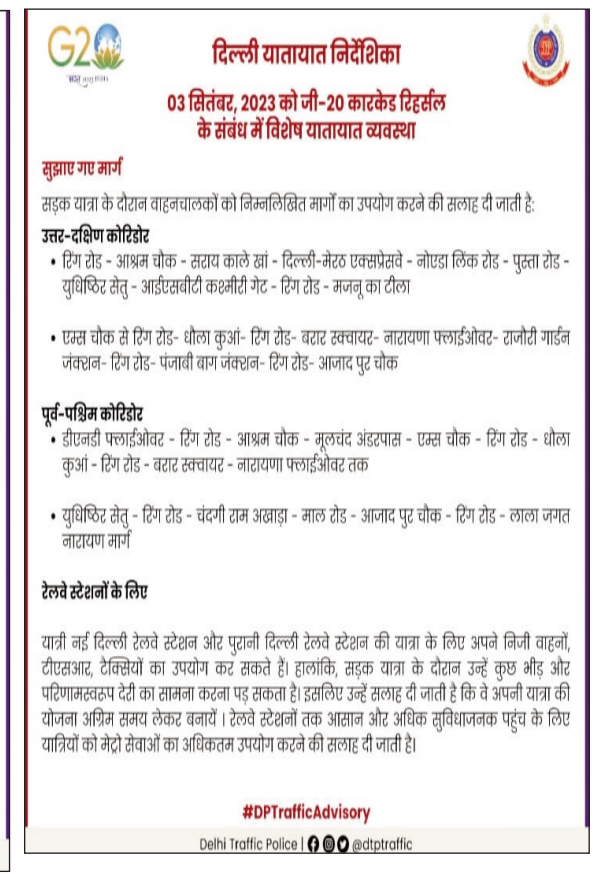

दिव्यांगजनों को पश्चिम बंगाल में मोटर वाहन टैक्स से छूट, केंद्र ने दी थी सलाह

राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप के मोटर वाहनों को मोटर वाहन टैक्स के भुगतान से छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली। राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप के मोटर वाहनों को मोटर वाहन टैक्स के भुगतान से छूट दी जाएगी। 29 अगस्त की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में सभी मोटर वाहन पंजीकरण अधिकारियों को इसके मुताबिक काम करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओनरशिप टाइप दिव्यांगजन के तहत पंजीकृत मोटर वाहनों को पश्चिम बंगाल मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जब तक कि कोई दिव्यांग व्यक्ति इसका पंजीकृत मालिक है।

इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों का लाभ उठाने के लिए अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में स्वामित्व प्रकार को 'दिव्यांगजन' के रूप में दर्ज करने के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से आवेदन हासिल हो रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2018 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत आर्थोपेडिक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिव्यांगजन मानने की सुविधा दी है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2023 की अपनी सलाह में राज्य सरकारों को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को विभिन्न लाभ देने की सलाह दी थी।

दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट एंड ट्रांसपोर्टरस एसोसिएशन ने नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री भारत सरकार को लिखा शिकायत पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट एंड ट्रांसपोर्टरस एसोसिएशन ने हिमाचल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बसों के नेशनल परमिट (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट)होने के बाद भी अलग से 5270 रुपए प्रतिदिन शरू करने के खिलाफ एक पत्र

श्री नितिन गडकरी जी

परिवहन मंत्री भारत सरकार को लिखा.

ट्रांसपोर्टरस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की पूरे भारत का 3 लाख सालना रोड टैक्स देने के बावजूद (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट) नेशनल परमिट होने के बाद भी 1 सितम्बर 2023 से

हिमाचल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा हिमाचल को छोड़ कर बाहरी राज्यों के बस मालिकों का मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न शरू कर दिया है.

सम्राट का कहना है की केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने अभी कुछ समय पेहले दुसरे राज्यों के रोड टैक्स की नीति बनाई थी जिसमे टैक्सी बस और टेम्पो ट्रेवलर के चालको को दुसरे राज्यों के बॉर्डर पर रोड टैक्स ना देना पड़े और वहाँ रोड टैक्स के लिए लम्बी लाइन चालाक ना लगाए. इसलिए टैक्सी- बसों मालिकों की सहूलियत के लिए (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट)नेशनल परमिट की व्यवस्था करी और हमारे गाडी मालिक एक बार में ही पूरे भारत के राज्यों का टैक्स तीन, छे , और एक साल के अनूसार देने का प्रवाधान किया वाहन ऐप के द्वारा किया गया.

इस आदेश की अवहेलना तमिलनाडु, केरल, ओड़िसा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर

पेहले से ही नेशनल परमिट को नहीं मान रहे थे, और हमारे टूरिस्ट टैक्सी बस वालो पर भारी जुर्माना और गाड़ियों को जब्त भी कर रहे थे

इसलिए ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस बारे मै पेहले भी परिवहन मंत्री, नितिन गडकरी जी को 17 जुलाई 2023 को एक पत्र लिखकर शिकायत करी थी. हमारे पत्र के जवाब मे 4 अगस्त को आर्डर भी किया, उस आर्डर मे साफ लिखा था की नेशनल परमिट (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट) होने पर भारत का कोई भी राज्य अलग से दोबारा टैक्स नहीं लेगा.

लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो आर्डर 11 जुलाई 2023 को जारी हुआ है,

और वो आज 1 सितम्बर 2023 से से लागू हो गया .आज हमारी एक टूरिस्ट बस का 5270 रुपए का टैक्स हिमाचल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लिया गया है जबकि हमारे बस के मालिकों ने नेशनल परमिट (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट)

की सालना 3 लाख रुपए के हिसाब से तिमाही 90 हजाए रुपए दिए है (3महीने के)और ये टैक्स केंद्र सरकार के परिवहन विभाग को दी गई है

इसके देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश का परिवहन बिभाग हमसे अलग अलग गाड़ियों की सीट के हिसाब से पैसा वसूल करना शुरू कर दिया है, 1 सितंबर 2023 से हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों को छोड़कर सब को अलग से प्रतिदिन, साप्तहिक और महीने का अलग से टैक्स देना ही होगा. हिमाचल सरकार के इस कदम से दिल्ली और दुसरे राज्यों के ट्रांसपोर्ट्स का केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय से विश्वास हट गया है .

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नितिन गडकरी जी से सवाल किया है हमारे ट्रांसपोर्टेस ने जो पैसा केंद्र सरकार को नेशनल परमिट का दिया है 3 लाख रुपए सालना तक दिया है उसका क्या होगा ?

DELHI TAXI, TOURIST TRANSPORTERS & TOUR OPERATORS ASSOCIATION (Regd.
Regd. Off. : F-16, Ist Floor, Saidulajaab, Near Saket Metro Station, New Delhi-110030
Ph. : 011-40518321 | M : 9717906644, 9958068373, 9810182147 | Fax : 011-40518321,
Email : delhitaxi2003@gmail.com

Ref. :
Date : 01.09.23

सेवा में,
श्री नितिन गडकरी जी
परिवहन मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय :- पूरे भारत का रोड टैक्स देने के बावजूद और (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट) नेशनल परमिट होने के बाद भी 1 सितम्बर 2023 से हिमाचल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा दुसरे राज्यों की और दिल्ली के बस मालिकों से 5270 रुपए का प्रतिदिन टैक्स लेने और हमारे चालकों को उत्पीड़न करने के खिलाफ पत्र.

आदरणीय मंत्री जी,आपने कुछ समय पेहले दुसरे राज्यों के रोड टैक्स की नीति बनाई थी जिसमे टैक्सी बस और टेम्पो ट्रेवलर के चालको को दुसरे राज्यों के बॉर्डर पर रोड टैक्स ना देना पड़े और वहाँ रोड टैक्स के लिए लम्बी लाइन चालाक ना लगाए. इसलिए आप ने टैक्सी- बसों मालिकों की सहूलियत के लिए (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट)नेशनल परमिट की व्यवस्था करी और हमारे गाडी मालिक एक बार में ही पूरे भारत के राज्यों का टैक्स तीन, छे और एक साल के अनूसार देने का प्रवाधान किया वाहन ऐप द्वारा
आदरणीय मंत्री जी, इस आदेश की अवहेलना तमिलनाडु, केरल, ओड़िसा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर
पेहले से ही नेशनल परमिट को नहीं मान रहे थे, और हमारे टूरिस्ट टैक्सी बस वालो पर भारी जुर्माना और गाड़ियों को जब्त भी कर रहे थे, इस बारे मै हमने पेहले भी आप को 17 जुलाई 2023 को पत्र लिखकर शिकायत करी थी. आपने हमारे पत्र के जवाब में 4 अगस्त को आर्डर भी किया, उस आर्डर मे आपने साफ लिखा की नेशनल परमिट (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट) होने पर भारत का कोई भी राज्य अलग से दोबारा टैक्स नहीं लेगा.
लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो आर्डर 11 जुलाई 2023 को जारी हुआ है,
और वो आज 1 सितम्बर 2023 से से लागू हो गया .आज हमारी एक टूरिस्ट बस का 5270 रुपए का टैक्स हिमाचल सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लिया गया है जबकि हमारे बस के मालिकों ने नेशनल परमिट (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट)
की सालना 3 लाख रुपए के हिसाब से तिमाही 90 हजाए रुपए दिए है (3महीने के)और ये टैक्स केंद्र सरकार के परिवहन विभाग को दी गई है
इसके देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग हमसे अलग अलग गाड़ियों की सीट के हिसाब से पैसा वसूल करना शुरू कर दिया है,
1 सितंबर 2023 से हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों को छोड़कर सब को अलग से प्रतिदिन, साप्तहिक और महीने का अलग से टैक्स देना ही होगा.
हिमाचल सरकार के इस कदम से दिल्ली और दुसरे राज्यों के ट्रांसपोर्ट्स का केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय से विश्वास हट गया है क्योंकि हमने जब इस बारे मे आपको हिमाचल और दुसरे राज्यों के दोबारा टैक्स लेने की शिकायत की थी तब आपने एक आर्डर जारी कर हमें सांत्वना दी थी की कोई भी दूसरा राज्य नेशनल परमिट (आल इंडिया टूरिस्ट परमिट)होने पर दोबारा टैक्स नहीं लेगा.सवाल ये है हमारे ट्रांसपोर्टेस ने जो पैसा केंद्र सरकार को नेशनल परमिट का दिया है 3 लाख रुपए सालना तक दिया है उसका क्या होगा?
आदरणीय मंत्री जी, वास्तव में पेहले और अभी भी दुसरे राज्यों में में बॉर्डर पर रोड टैक्स कटाने पर परिवहन विभाग के कर्मचारी एंट्री के नाम पर चालको से पैसा वसूल करते है.
इसलिए अभी भी ये कर्मचारी और इनके अधिकारी चाहते है की ट्रांसपोर्टेस नेशनल परमिट ना लेकर बॉर्डर पर रोड टेक्स भरते रहे और एंट्री के नाम पर करोड़ो रुपए इनके विभाग को मिलते रहे.
आदरणीय मंत्री जी आप से विनती है की पूरे भारत के राज्यों के परिवहन मंत्रालय और इनके विभाग को सख्त निर्देश दिये जाये की नेशनल परमिट होने पर बसों और टेम्पो ट्रेवलर के चालकों से अलग से रोड टैक्स ना माँगा जाए. और चालको और ट्रांसपोर्टेस का उत्पीड़न भी रोका जाए.
धन्यवाद
संजय सम्राट(अध्यक्ष)
दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेस ऐसोसीएसन.9810182147---9717906644

संजय सम्राट का कहना है की वास्तव में पेहले और अभी भी दुसरे राज्यों में में बॉर्डर पर रोड टैक्स कटाने पर परिवहन विभाग के कर्मचारी एंट्री के नाम पर चालको से पैसा वसूल करते है.

इसलिए अभी भी ये कर्मचारी और इनके अधिकारी चाहते है की ट्रांसपोर्टेस नेशनल परमिट ना लेकर बॉर्डर पर रोड टैक्स भरते रहे और एंट्री के नाम पर करोडो रुपए इनके विभाग को मिलते रहे.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने नितिन गडकरी परिवहन मंत्री से मांग करी की पूरे भारत के राज्यों के परिवहन मंत्रालय और इनके विभाग को सख्त निर्देश दिये जाये की नेशनल परमिट होने पर बसों और टेम्पो ट्रेवलर के चालकों से अलग से रोड टैक्स ना माँगा जाए. और चालको और ट्रांसपोर्टेस का उत्पीड़न भी रोका जाए.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने हिमाचल टैक्स के खिलाफ 26 जुलाई को मंडी हाउस पर प्रदर्शन करके विरोध जताया था और 20 अगस्त को हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुखु जी से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी दिया उस वक़्त मुख्यमंत्री ने हिमाचल मे आई आपदा की बात कहकर 4 सितम्बर 2023 को मिलने का वायदा किया था और उस वक़्त उन्होंने टैक्स को हटाने पर विचार करने का भी वायदा भी किया था.

ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है की अगर हिमाचल का टैक्स नहीं हटाया गया तो हिमाचल की बसों को दिल्ली मे और दुसरे राज्यों मे नहीं घूसने दिया जाएगा.

बल्कि पूरे हिमाचल के बॉर्डर्स मे कोई भी बाहरी राज्य की बसें हिमाचल प्रदेश मे नहीं जाएंगी.

हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमि टूरिज्म से चलती है. अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम हिमाचल प्रदेश की बजाये उत्तराखंड मे या किसी दुसरे राज्यों मे पर्यटको को भेजेंगे।

इस राज्य में अब एआई से होगा ड्राइविंग टेस्ट, इन शहरों में बनेंगे खास ट्रैक, जानें डिटेल

सड़क पर वाहनों की सुरक्षा के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए नई तकनीक के उपयोग की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस राज्य में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। आइए जानते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के एक राज्य में जल्द ही नई तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किस राज्य में नई तकनीक से टेस्ट की तैयारी हो रही है। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि राज्य के किन शहरों में खास ट्रैक बनाए जाएंगे।

नई तकनीक से होगा टेस्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में जल्द ही नई तकनीक से ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिए जाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में मोटर वाहन परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई टेस्ट लागू करने की तैयारी कर रहा है।

क्या होगा खास

जानकारी के मुताबिक ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लाइसेंस के लिए जरूरी 24 पाइंट्स में से सात का मूल्यांकन करेंगे। इसमें दो पहिया, हल्के और भारी वाहनों के साथ ही सभी तरह के मोटर वाहन के टेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। जिसमें कई तरह के टेस्ट होंगे। इनमें आठ बनाना, एच ट्रैक, जिग-जैग, ग्रेडिएंट, जेबरा क्रॉसिंग, रिवर्स ट्रैक जैसे कई टेस्ट होंगे।

किन शहरों में होगी शुरुआत

रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य कुल 17 शहरों में इसकी शुरुआत हो सकती है। इनमें मुंबई, अमरावती, नागपरु, बुलढाणा, नागपुर ग्रामीण, नागपुर पूर्व, नांदेड़, पुणे, अहमदनगर, कोल्हापुर, ठाणे, पनवेल जैसे शहरा शामिल हैं।

क्या होगा फायदा

महाराष्ट्र में अगर एआई के साथ ड्राइविंग टेस्ट की शुरुआत होती है। तो इसका फायदा यह होगा कि टेस्ट प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो जाएगी। जिसके कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी और सही नतीजे मिलने के कारण सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाइसेंस मिल पाएगा, जो सुरक्षित तरीके से वाहन को चलाएंगे। ऐसा होने पर सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी आ पाएगी।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में कितना आया बदलाव?

शालिनी बाजपेयी

धरती के इस छोर से उस छोर तक
मुट्ठी भर सवाल लिये मैं
छोड़ती-हाँफती-भागती
तलाश रही हूँ सदियों से निरंतर
अपनी ज़मीन, अपना घर
अपने होने का अर्थ!

भारतीय समाज की नारी की स्थिति को बखूबी बयां करती निर्मला पुतुल की ये पंक्तियाँ पूरे समाज की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। भले ही आज हम यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लें कि आजादी के 75 सालों में हमारी महिलाएँ चाँद पर पहुँच गई हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रही हैं या राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर देखें तो यह संख्या महिलाओं की आबादी का अंशमात्र ही है। हमारे समाज की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया है; उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या यूँ कहें कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि वे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिये पुरुषों का सहारा ढूँढती हैं। वहीं यह भी सत्य है कि "जब-जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब-तब न जाने कितने रीति-रिवाजों, परंपराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।" इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर भारत में शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर महिलाओं ने अब तक कितनी दूरी तय की है-

कितनी बढ़ी महिलाओं की साक्षरता दर?

भारत में आज भी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहीं, पढ़ाई-लिखाई के दौरान बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या भी लड़कों की संख्या से बहुत ज़्यादा है क्योंकि लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे घर के कामकाज में मदद करें। वहीं, उच्च शिक्षा की बात करें तो बहुत सी लड़कियाँ सिर्फ इसलिए उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं क्योंकि उनके परिवार वाले पढ़ाई के लिये उन्हें घर से दूर नहीं भेजते हैं, जिसके चलते उनका अधिकतर समय घरेलू कामों में खर्च होता है और महिलाओं व पुरुषों के बीच समानता का अंतराल बढ़ता चला जाता है। इससे इस मिथक को बढ़ावा मिलता है कि, शिक्षा-दीक्षा लड़कियों के किसी काम की नहीं है क्योंकि अंत में उन्हें प्राथमिक रूप से घर ही संभालना है, शादी करनी है और पति व बच्चों की सेवा करनी है। इतना ही नहीं, लड़कियों को शादी कब करनी है, किससे करनी है, बच्चे कब पैदा करने हैं? ये सब कुछ भी हमारी पितृसत्ता तय करती है।

आँकड़ों पर नजर डालें तो, साल 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.3 फीसदी थी जिसमें से महिलाओं की साक्षरता दर 9 फीसदी से भी कम थी। वहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के डाटा के अनुसार साल 2021 में देश की औसत साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत थी जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियाँ देश की बेटियों को एक बार फिर से उठ खड़े होने का ज़ज्बा प्रदान करती हैं-

आओ उड़ाने भरें
पंख भी हैं, खुला आकाश भी है
फिर ये न उड़ पाने की मज़बूरी कैसी
लगता है, आत्मा पर जंग लगे संस्कारों की
कील ठोंक दी गई है
कि पंख बस
यूं ही फड़फड़ाएं और रह जाएं

रसोई में केवल महिलाएँ ही क्यों?

भारत के रसोइघरों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज भी घर की बेटी, बहू, माँ व पत्नी चाहे कितनी भी पढ़ी-लिखी क्यों न हो; कितने ही बड़े पद पर काम क्यों न कर रही हो; घर के सभी सदस्यों के लिये खाना पकाने व परोसने की उम्मीद सिर्फ महिला सदस्य से ही की जाती है। इसी वजह से भारतीय समाज में लड़कियों को बचपन से ही रसोईघर के काम सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं, जबकि लड़कों को रसोई से दूर रखा जाता है। जिससे आगे चलकर वे लड़के, जिनसे कभी रसोई के काम नहीं करवाए गए; जिन्होंने कभी अपने पिता को माँ के साथ खाना बनाते या अन्य घरेलू कामों में मदद करते नहीं देखा, वे भी अपने बच्चों को वैसा ही बनाते हैं जैसा उन्होंने अपने परिवार में देखा होता है। जिससे पितृसत्ता की विचारधारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी रुकावट के स्थानांतरित होती रहती है और अधिकांश महिलाएँ पूर्ण रूप से देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाती हैं।

यहाँ पर इस बात पर भी विचार करना ज़रूरी है कि, महिलाएँ घर के पुरुषों को खाना खिलाने के बाद अंत में खाना खाती हैं। घर का कोई पुरुष इस बारे में नहीं सोचता कि उन्हें भी हमारे साथ बैठकर खाने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं कि सभी पुरुष क्रूर और हिंसक है। इसका मतलब यह है कि, पितृसत्ता ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम उससे परे जाकर सोच नहीं पाते हैं। जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। इस संदर्भ में निर्मला पुतुल की निम्नलिखित पंक्तियाँ बेहद प्रासंगिक हैं-

तन के भूगोल से परे
एक स्त्री के
मन की गाँठें खोलकर
कभी पढ़ा है तुमने
उसके भीतर का खौलता इतिहास?
XXXX
अगर नहीं!
तो फिर जानते क्या हो तुम
रसोई और बिस्तर के गणित से परे
एक स्त्री के बारे में...?

धर्मों में भी महिलाओं का स्थान निम्न

भारत जैसे पितृसत्तात्मक देश में शिक्षा, मीडिया, कानूनी संस्थाएँ, आर्थिक संस्थाएँ, राजनीतिक संस्थाएँ सभी पूरी तरह से पितृसत्तात्मक हैं। यहाँ तक कि, सभी धर्म भी पितृसत्तात्मक हैं। अधिकांश धर्म महिला को अपना मुख्य आराध्य नहीं मानते। चूंकि धर्मों में पितृसत्ता को सर्वोच्च दिखाया गया है इसलिए महिलाओं को हमेशा से धर्म के नाम पर दबाने का प्रयास किया जाता है, और महिलाएँ बिना बराबरी का अधिकार माँगे अपने पति को परमेश्वर, स्वामी मानने लगती हैं। वह इस बात पर ज़रा भी विचार नहीं करतीं कि पति-पत्नी में अगर एक मालिक है तो दूसरा कौन होगा? वह आसानी से अपने आपको गुलाम मान लेती हैं क्योंकि उनका प्राइमरी स्कूल जो कि उनका परिवार होता है, में उन्हें बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है।

फीसदी महिलाएँ हैं, जबकि संसद में महिलाओं की वैश्विक औसत भागीदारी 25 फीसदी से ज़्यादा है। इसके अलावा, ग्रामीण अंचलों में पंचायत स्तर पर अधिकांश महिलाओं को केवल मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है यानी चुनाव तो महिला जीतती है लेकिन सत्ता से संबंधित सभी निर्णय उसके परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं।

वहीं, न्यायालय में भी महिलाओं की संख्या संतोषजनक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सहित उच्च न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीशों में महज 11 प्रतिशत महिलाएँ हैं। समय की माँग है कि अब महिलाएँ जाग्रत हों और अपनी क्षमता को पहचान कर, परंपरागत रूढ़ियों को खंडित कर देश की मुख्यधारा में अधिक से अधिक योगदान दें।

ऐ शक्ति स्वरूपा
ऐ भावी पीढ़ी की निर्माता
मानवता तुम्हे प्रणाम करे
आओ! उड़ान भरें
आओ! हम सब मिलकर इस पार
बादलों के उस पार
लंबी-ऊंची उड़ान भरें

निष्कर्ष

रूप में हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में एक लंबा रास्ता तय किया है, परंतु अभी भी मंजिल से मीलों दूर हैं। तेजी से भागते समय के इस पहिये के साथ हमारी रफ्तार बहुत धीमी है, और इस रफ्तार को तभी बढ़ाया जा सकता है जब भारतीय समाज पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठकर महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्रदान करेगा। हालाँकि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं लेकिन यहाँ का समाज अपने नियमों के अनुसार, महिलाओं को संचालित करता है, जिसमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है।

साथ ही, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिये कि हमें नारीशक्ति का उद्धारक नहीं, वरन उनका सहायक बनना है। भारतीय महिलाएँ भी संसार की अन्य महिलाओं की तरह अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएँ; उनका वस्तुकरण करने की बजाय उन्हें मनुष्य समझा जाए। बेहतरीन कवयित्री अनामिका ने स्त्रियों को गहराई से समझने की गुजारिश करते हुए लिखा है-

सुनो, हमें अनहद की तरह
और समझो जैसे समझी जाती है
नई-नई सीखी हुई भाषा।

आर्थिक रूप से कितनी सक्षम हैं भारतीय महिलाएँ

आज भी महिलाओं की अधिकांश समस्याओं का कारण आर्थिक रूप से परनिर्भरता है। यह बेहद चिंताजनक है कि देश की कुल आबादी में 48 फीसदी महिलाएँ हैं जिसमें से मात्र एक तिहाई महिलाएँ रोजगार में संलग्न हैं। इसी वजह से भारत की जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 18 फीसदी है।

यदि परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को समाप्त कर पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के अवसर प्रदान किए जाएं तो अन्य महिलाएँ भी गीता गोपीनाथ, इंद्रा नुई, किरण मजूमदार शॉ की तरह सशक्त होंगी, साथ ही देश भी आर्थिक मोर्चे पर तेजी से प्रगति करेगा। सभी महिलाओं को इन चार पंक्तियों को ज़रूर आत्मसात करना चाहिये-

न रहो कभी किसी की आश्रिता,
खुद बनकर स्वावलंबी बनो हर्षिता
हमें खुद अपना संबल बनना है
हमें परजीवी लता नहीं बनना है॥

सत्ता व न्यायालयों में महिलाओं की भागीदारी

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समय में महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही हैं, और न केवल संभाल रही हैं बल्कि कुशल संचालन कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, प्रियंका गाँधी, स्मृति ईरानी, मेनका गाँधी, मायावती को देखा जा सकता है। लेकिन देश में महिलाओं की आबादी के अनुसार देखें तो राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। भारतीय संसद में केवल14

शालिनी बाजपेयी
शालिनी बाजपेयी यूपी के रायबरेली जिले से हैं। इन्होंने IIMC, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा करने के बाद जनसंचार एवं पत्रकारिता में एम.ए. किया। वर्तमान में ये हिंदी साहित्य की पढ़ाई के साथ साथ लेखन का कार्य कर रही हैं।

ऐसी महिलाएं होती हैं घर में लक्ष्मी का रूप

महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता मां लक्ष्मी उस घर से अपना नाता तोड़ लेती हैं। शास्त्रों में वर्णित है की घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उस घर में स्थान नहीं मिलता।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता मां लक्ष्मी उस घर से अपना नाता तोड़ लेती हैं। शास्त्रों में वर्णित है की घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उस घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवंतता का संचार कर उसे घर बनाती हैं। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। उस घर में लक्ष्मी को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देना होता बल्कि उस घर की महिला ही लक्ष्मी का रूप होती हैं।

महिलाएं जो घर में होती हैं लक्ष्मी का रूप

मीठे वचन बोलने वाली, आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है।

जो स्त्री तन से ही नहीं मन से भी सुंदर हो।

घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे।

पराया दुख देखकर दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करे और जो दूसरों को दुख-दर्द में देखकर उसको दूर करने में आनंद का अनुभव करे।

घर की रसोई में भेद-भाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे। सभी सदस्यों को भोजन कराने के उपरांत भोजन करे।

जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन कर रसोई घर में प्रवेश करती है।

सुबह शाम घर में देवी-देवताओं के सामने धूप, दीप और सुंगधित अगरबत्ती जला कर पूजा-पाठ करती है।

पतिव्रत धर्म का पालन करे।

धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे।

महिलाएं जो घर में होती हैं अलक्ष्मी का रूप

जो स्त्री मैली-कुचैली सी और पाप कर्मों में रत रहती है, पराय पुरुषों में उसका मन रमता है।

जो बात-बात पर गुस्सा करती है, अपने पति को दबाने के लिए रोष प्रदर्शन, छल या मिथ्या भाषण करती है।

अपने घर को सजा-सवार कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते, अपना घर छोड़ दूसरों के घर नित्य जाती रहती है, जिसे लज्जा नहीं आती, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती।

अपने पति से प्रेम न करने वाली स्त्री पति के लिए सदैव दुख का कारण बनती है।

दिल्ली में हाई अलर्ट: हर G20 आयोजन स्थल पर विशेष तैनाती, आतंकवाद से निपटने के लिए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

परिवहन विशेष न्यूज

जी-20 सम्मेलन आजाद भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए दिल्ली में सुरक्षा को व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट, कारकेड मैनेजमेंट, होटल आदि की सुरक्षा के साथ-साथ आतंकी व शरारती तत्वों की वारदात को रोकने के लिए सुरक्षा का हर कदम उठाया गया है।

नई दिल्ली। जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सात से 10 सितंबर तक दिल्ली हाई अलर्ट पर रहेगी। बड़े आयोजन स्थलों की कमान दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त स्तर के अधिकारी के पास होगी। जिन होटलों में राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे, वहां की जिम्मेदारी पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी के पास होगी। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (प्रोटेक्टिव सिक्यूरिटी डिवीजन) मधुप तिवारी ने दिल्ली पुलिस की ओर से शुक्रवार को जी-20 की सुरक्षा को लेकर आधिकारिक जानकारी दी।

मधुप तिवारी के मुताबिक, आतंकी वारदात को रोकने के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस बात पर भी विशेष ध्यान है कि सुरक्षा इंतजामों के चलते आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया होटल के कुछ ग्रुप की सुरक्षा की जिम्मेदारी व निरीक्षण का जिम्मा विशेष पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। होटल के कमांडर बनाए पुलिस उपायुक्त की सहायता के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। आतंकी व किसी अन्य वारदात को रोकने के लिए हर तरह की सावधानी बरती जा रही है।

मधुप तिवारी ने कहा कि जी-20 सम्मेलन आजाद भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए दिल्ली में सुरक्षा को व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट, कारकेड मैनेजमेंट, होटल आदि की सुरक्षा के साथ-साथ आतंकी व शरारती तत्वों की वारदात को रोकने के लिए सुरक्षा का हर कदम उठाया गया है। इस तरह के बड़े आयोजनों के लिए दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है। इसके लिए कई एजेंसियों से सहयोग मिला है। ये सहयोग मैनपावर, आधुनिक उपकरण व गाड़ियों के रूप में मिला है।

मधुप तिवारी के मुताबिक, जी-20 के लिए जो स्टाफ तैनात किया गया है उसे रोलबेस माइक्रो फक्शनिंग लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। स्टाफ की लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। ड्यूटी पाइंट के जरिये जागरूक व आगाह किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस व उसका पूरा स्टाफ इस आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। लगातार कारकेड, डी-ब्रीफिंग व ड्यूटी पाइंट पर तैनाती की रिहर्सल की जा रही हैं।

बीजेपी में रार? मोदी-गडकरी में आर-पार सरकार?

परिवहन विशेष । एसडी सेठी। बीजेपी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। अगर इस बात पर यकीन करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पीएम नरेंद्र मोदी से पटरी नहीं बैठ रही है। हालांकि उन्होंने एक निजी मंच से यह तक कह डाला कि मन करता है कि वह कब राजनीति को छोड दें? अजीब सी छटपटाहट है। राजनीति का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने के लिए करना ,अपने में बहुत कुछ सवाल खडा करता है। ऐसे हताश शब्दों का प्रयोग गडकरी के लिए कहीं ना कहीं टीस दर्शाता है। ऐसा नजारा गत16 अगस्त को पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई की पुण्यतिथि में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिखाई दिया, जब पीएम मोदी बाकायदा हाथ जोडे कतार में खडे नेताओ से मिलते हुए चल रहे हैं। लाइन में खडे नेता भी हाथ जोडकर मोदी का अभिवादन कर रहे हैं । लेकिन पीएम मोदी जैसे ही नितिन गडकरी के सामने हाथ जोडे निकले तो गडकरी ने अपने हाथ पीछे कर लिए और कोई प्रतिक्रिया तक नहीं की। बल्कि मुंह तक फेर लिया। विकास का एक्सप्रेस वे, इथोनेल, हाइड्रोजन, और अन्य इको फ्रेंडली प्रयोग के लिए चर्चित गडकरी पीएम मोदी से खासे खफा है। गडकरी को नीचा दिखाने के प्रयास से वह विचलित और परेशान है। तभी तो गडकरी ने कहा कि मन करता है कि वह कब राजनीति को छोड दें। वह अपने को पार्टी में अलग थलग दिखाई देते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधान मंत्री की दौड में उनकी दावेदारी तब होती दिखाई पडती है। अगर बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं आया तो नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करेगें। ऐसे में तब कोईलेशन में वह प्रधान मंत्री के दावेदार हो सकते है। ऐसा वक्त की नजाकत को देखते हुए पीएम मोदी अन्य पार्टीयो के सहयोग से सरकार नहीं चलाएगे। तब मोदी अपने दिए वचनों पर अमल करते हुए झोला उठाकर जा सकते हैं। ऐसे में मोदी के सामने नितिन गडकरी का बतौर पीएम के विकल्प के बतौर दावेदारी हो सकती है।

पिंकी की आखिरी रात: साकिब संग चार साल से लिव इन में थी, दोनों ने साथ खाया खाना फिर... डायरी में दफन हैं कई राज

घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। मौके से एक डायरी और युवती का फोन मिला है। जानकारी सामने आ रही है कि डायरी में पिंकी ने शाकिब द्वारा प्रताड़ति किए जाने की बात लिखी है।

यूपी के गाजियाबाद स्थित वैशाली में से एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस को गुरुवार देर रात कमरे में 23 साल की जिम रिसेप्शनिस्ट का शव पंखे से लटका मिला। लड़की की पहचान पिंकी गुप्ता के तौर पर हुई है, जो बीते चार साल से साकिब नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। पिंकी के परिवार वालों ने शाकिब पर हत्या का आरोप लगाया है जो कि घटना के बाद फरार हो गया था।

पिंकी के परिवार वालों ने थाने के बाहर रखा शव

पुलिस ने बताया कि पिंकी दिल्ली के गाजीपुर के रहने वाले साकिब खान के साथ लिव इन में रहती थी। घटना के बाद आरोपी कमरा बंद कर भाग गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर थाने के बाहर शव रख कर हंगामा किया। मां-पिता और अन्य लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। मां का कहना था कि उनकी बेटी वापस घर आना चाहती थी लेकिन युवक ने धमकी देकर उसे जाने नहीं दिया। करीब ढाई घंटे तक परिजन थाने के बाहर डटे रहे।

चार साल से संग रहते थे दोनों

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11.30 बजे लड़की की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन की। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला की वैशाली में रहने वाली पिंकी जिम में रिसेप्शनिस्ट थी। जिम में ही गाजीपुर के युवक से उसकी जान पहचान हो गई थी। दोनों चार साल से वैशाली में एक साथ किराए के कमरे में रहते थे। गुरुवार रात दोनों ने एक साथ खाना खाया था। इस बीच साकिब कमरा बंद कर बाहर चला गया। देर रात पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी कि कमरे में युवती पंखे से लटकी हुई थी।

डायरी से हो सकता है अहम खुलासा

घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। मौके से एक डायरी और युवती का फोन मिला है। जानकारी सामने आ रही है कि डायरी में पिंकी ने शाकिब द्वारा प्रताड़ति किए जाने की बात लिखी है। हालांकि इस बात की पुष्टि होना बाकी है।

सम्मेलन के दौरान खतरा, दिल्ली-पंजाब में घूम रहे हैं पांच खालिस्तानी समर्थक, एजेंसियां सतर्क

दिल्ली व पंजाब में पांच खालिस्तानी आतंकी घूम रहे हैं। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थित स्लोगन लिखने वाले खालिस्तान के सात समर्थक थे। इनमें से अभी दो पकड़े गए हैं।

नई दिल्ली। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान खालिस्तानी आतंकियों का खतरा बना हुआ है। दिल्ली व पंजाब में पांच खालिस्तानी आतंकी घूम रहे हैं। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थित स्लोगन लिखने वाले खालिस्तान के सात समर्थक थे। इनमें से अभी दो पकड़े गए हैं।

ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने बाकी खालिस्तानी आतंकियों को पकडने के लिए अभियान तेज कर दिया है। इसके चलते दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों को मेट्रो स्टेशनों को रात में भी चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। सीनियर अधिकारी रात में तीन-तीन बार मेट्रो स्टेशनों को चैक करने जाते हैं।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के चार मेट्रो व एक स्कूल की दीवार खालिस्तानी समर्थित स्लोगन लिखने वाले आरोपी कुल सात हैं। इन खालिस्तानी समर्थकों ने पांच-छह दिन रैकी थी। इन्होंने देखा था कि मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे कहां-कहां लगे हैं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए इन्होंने मेट्रो स्टेशनों की पिछली साइड में स्लोगन लिखे थे। इसके बावजूद आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए।

गिरफ्तार आरोपी प्रीतपाल सिंह ने पूछताछ में बताया है कि उसे गुरपंत सिंह पन्नू ने आदेश दिया था कि जी-20 शिखर सम्मेलन तक कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहना हैं। पुलिस ने गिरफ्तार प्रीतपाल सिंह व राजविंदर को देर शाम

कोर्ट में पेश किया और पांच दिन का पुलिस रिमांड मांगा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद ही पता लगेगा कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने उसे किस तरह की वारदात करने के कहा था।

तुरंत ध्यान खींचने के लिए मेट्रो स्टेशनों को चुना

आरोपी प्रीतपाल सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया है कि अगर वह किसी दीवार पर लिखते थे तो एमसीडी अधिकारी उसे पोत कर मिटा देते थे। अगर मेट्रो की दीवार पर कुछ लिख दिया जाए तो उसमें एफआईआर दर्ज होती है। यहां कुछ भी लिखने पर तुरंत सरकार व लोगों को ध्यान जाता है। इस कारण मेट्रो स्टेशनों को खालिस्तान समर्थित स्लोगन लिखने के लिए चुना गया था।

पीएम मोदी के मेरी माटी मेरा देश का रोहिणी विजय विहार फेज-2 में घर-घर अभियान का आगाज

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ₹मेरी माटी मेरा देश के अभियान के तहत शुक्रवार को लता मंगेशकर वाटिका,अटल चौंक ,विजय विहार फेज-2, रोहिणी में ढोल-बाजे और तिरंगे झंडे के साथ हजारों लोगों ने घर-घर से देश के नाम पर कलश में मिट्टी को इकट्ठा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक आशीष भदौरिया ने बताया कि इस अभियान के तहत वार्ड- 24 के पूर्व पार्षद मनीष चौधरी,पार्षद स्मिता कौशिक, मण्डल अध्यक्ष उमेश गिरी, मनोज मलिक, चाचा चौधरी, आलोक मिश्र , गुडिया महता समेत सैकडों की संख्या में अल्पसंख्यक समाज से लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक आशीष भदौरिया ने बताया कि हजारों की संख्या में एकत्रित देश भक्तों ने तिरंगा यात्रा के साथ घर-घर से मिट्टी के कलश इकट्ठा किए गए।

अमेजन मैनेजर हत्याकांड में अब तक चार आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी फरार

अमेजन कंपनी के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है।

नई दिल्ली। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अमेजन कंपनी के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को पकड़ा है, एक आरोपी अभी भी फरार है। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोहेल और जुबैर के रूप में हुई है। पुलिस ने इन आरोपियों को तब पकड़ा जब ये पंजाब भागने की फिराक में थे। इन्हें बुराड़ी से गिरफ्तार किया गया है ।स वहीं इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने बिलाल गनी और मोहम्मद समीर उर्फ माया को गिरफ्तार किया था।

मंगलवार रात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में थाने से चंद कदमों की दूरी पर बाइक व स्कूटी सवार बदमाशों ने अमेजन के सीनियर मैनेजर और उसके मामा को गोली मार दी थी। गंभीर हालत में मैनेजर हरप्रीत गिल (36) और इनके मामा गोविंद (32) को नजदीकी जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां हरप्रीत को मृत घोषित कर दिया गया। मामा का इलाज जारी है। पुलिस ने बुधवार को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवा कर हरप्रीत का शव परिवार को सौंप दिया।

हरप्रीत गिल परिवार के साथ गली नंबर-1, सुभाष विहार, भजनपुरा में रहते थे। इनके परिवार में पिता करनैल सिंह, मां स्वर्णदीप कौर और एक छोटा भाई सन्नी गिल है। हरप्रीत पिछले करीब 14 सालों से अमेजन में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात थे। फिलहाल उनकी तैनाती जखीरा स्थित दफ्तर में थी। रिश्ते में हरप्रीत के मामा लगने वाले गोविंद सिंह गली में ही परिवार के साथ रहते हैं। वह भजनपुरा मार्केट में हंग्रीबर्ड के नाम से मोमोज की दुकान चलाते हैं। मंगलवार रात को हरप्रीत अपने दफ्तर से घर आ गए। देर रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से किसी काम से निकले।

रात करीब 11.45 बजे वापस लौटते समय गली नंबर-8/4 में उनका वहां से स्कूटी व बाइक पर गुजर रहे पांच लड़कों से कुछ विवाद हो गया। बदमाशों ने पिस्टल निकालकर दोनों की कनपटी पर सटाकर गोली मार दी और फरार हो गए। जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. जॉय टिर्की का कहना है कि इनसे लूटपाट का प्रयास नहीं किया गया। परिजनों ने लेनदेन और रंजिश की बात से साफ इनकार किया।

हरप्रीत का हो गया था प्रमोशन, जाना था बेंगलुरु

हरप्रीत की मौत के बाद से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मंगलवार को जब परिवार को उसकी हत्या की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया। मृतक का भाई सन्नी घटना स्थल की ओर भागा तो हादसे का शिकार हो गया। उसे गंभीर चोटें लगीं। एक परिजन ने बताया कि हरप्रीत का प्रमोशन हो गया था और अगले सप्ताह उसे बेंगलुरू जाना था। उसके पिता करनैल सिंह काफी समय से बीमार चल रहे हैं। बेटे की मौत की खबर सुनकर वह बेहोश हो गए। यही हाल उसकी मां का भी था। दूसरी ओर गोविंद सिंह के परिजन उसके जल्द ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे हैं।

स्वतंत्रता, एकता और अखंडता में महत्व पूर्ण योगदान देने वाले नायकों की याद व उनके सम्मान में अभियान की हुई शुरुआत

सांसद रमेश बिधूड़ी ने की 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान की शुरुआत

दिलीप देवतवाल

परिवहन विशेष, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता में महत्व पूर्ण योगदान देने वाले नायकों की याद व उनके सम्मान में दक्षिणी दिल्ली लोक सभा स्थित महरौली जिले के डेरा गॉव व दक्षिण दिल्ली जिला स्थित कालकाजी में आयोजित 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम व कलश यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जिलाअध्यक्ष चौटाला भी उपस्थित रहे।

इस दौरान डेरा गॉव में स्वतंत्रता सेनानी राजे तंवर जी की समाधि पर पंच प्रण संकल्प के साथ कलश यात्रा शुरू कर हर घर से गॉव में शहीद वाटिका के लिए एक चुटकी मिट्टी एकत्रित की गई और उनके परिवारजन को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवहान पर देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रारंभ किया गया है। जिससे देश के हर गॉव हर कस्बे, हर नगर, हर शहर व हर वर्ग के लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है व बहुत से लोगों ने अपना जीवन खपाया है। लेकिन देश की आजादी के 75 साल तक भी उन परिवारों को जिनके अपनों ने देश की आजादी के लिए आहूति दी है उन्हें सम्मान देने का काम नहीं हो पाया, कारण कुछ भी रहे हों। उन्होंने कहा कि हर गॉव की मिट्टी में कुछ ना कुछ था जो गॉव का नौजवान देश के लिए निकल पड़ा, चाहें 1947 से पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, चाहें चाईना युद्ध के रूप में, चाहें पाकिस्तान युद्ध के रूप में, चाहें सीमा पर रहते हुए घुसपैठियों के द्वारा उनकी हत्या की गई, ऐसे शहीदों को सम्मान, नमन व उनकी वंदना और उनके परिवारों को सम्मान के लिए गॉव के हर मुख्य स्थान पर शहीदों की सूची तैयार कर के शिलालेख पर उनके नाम अंकित कर उनके परिवारों को सम्मान मिले व उनका वंदन हो पाए। बिधूड़ी ने आगे बताया कि शहीदों के सम्मान में हर घर से एक चुटकी मिट्टी घर के आंगन की या चावल के दाने इस कलश यात्रा में जो मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में हर गॉव से निकाली गई है, इस अमृत कलश यात्रा के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के लोग और गॉव के सम्मानित निवासियों के साथ मिलकर घर-घर से कलश लेकर आएगें और अपना समपर्ण, योगदान व सहानुभूति माटी के रूप में देंगे जिससे उस गॉव के अन्दर शहीदों की याद में वाटिका का निमार्ण होगा, जिसमें 75 पौधे लगाए जाएगें और एक उस मिट्टी में से एक कलश मिट्टी दिल्ली में कतर्व्य पथ इंडिया गेट पर ले जाई जायेगी और वहॉ देश के ऐसे लाखों शहीदों की याद में एक शहीद स्थल का निमार्ण पाकर् के रूप में किया जाएगा जिसमें उनका सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि आप भी अपने गॉव की सम्मानित मिट्टी वहॉ तक पहुॅचाएं क्योंकि हम मिट्टी को इस धरती को मॉ कहते हैं, इसलिए इस मिट्टी की ही ताकत से वह नौजवान देश की आजादी के लिए निकले थे। इस योजना में आप

हरियाणवी नृत्य और संस्कृति से रू-ब-रू होंगे विदेशी मेहमान

परिवहन विशेष न्यूज

- नूंह की छवि को जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ चमकाने की कवायद
- तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंकी, मुख्य सचिव ने परखे इंतजाम

गुरुग्राम। जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत नूंह जिले में होने वाली चौथी शेरपा बैठक में आने वाले विदेशी मेहमान हरियाणवी नृत्य और संस्कृति से भी रू-ब-रू होंगे। उनके रात्रि भोज के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजी नाइट की भी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमें हर पहलू को ध्यान रखना है जिससे बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि नूंह और गुरुग्राम जिले के साथ-साथ हरियाणा की अच्छी छवि लेकर अपने देश जाएं।

शेरपा बैठक नूंह में तावडू के नजदीक स्थित आईटीसी ग्रैंड भारत में तीन से सात सितंबर तक होगी। आयोजन स्थल की कनेक्टिविटी गुरुग्राम से अच्छी होने के कारण तैयारियों को जी-20 सचिवालय तथा मुख्य सचिव की निगरानी में नूंह और गुरुग्राम दोनों जिलों के प्रशासन द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि आयोजन के दिनों में सभी अधिकारी सतर्क रहें और ध्यान रखें कि उनके विभाग से जुड़े किसी भी कार्य में कमी न रहे। मुख्य सचिव कार्यालय में नियुक्त विशेष सचिव डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि प्रतिभागियों की सुविधा के लिए उनके साथ 23 लाइजन ऑफिसर भी लगाए जाएंगे, जिनमें 19 एचसीएस तथा चार आईएएस स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

चार सितंबर को अतिथियों को हरियाणा सरकार की तरफ से रात्रि भोज दिया जाएगा। इसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हो सकते हैं। इसी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति विदेश मंत्रालय की टीम द्वारा दी जाएगी। प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा पांच सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और छह सितंबर को फिर से विदेश मंत्रालय की टीम द्वारा सांस्कृतिक नाइट का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा को निर्देश दिए कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगाएं कि वह रात में सड़कों पर लगाई गई लाइट की जांच करें। इसके साथ एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि वह सड़क सुधारीकरण काम की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके पास भिजवाएं।

ठहरने से लेकर रास्तों तक होगी निगरानी

पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने बताया कि आयोजन स्थल, उनके ठहरने के स्थानों तथा आवागमन के रास्ते पर पुलिस की निगरानी रहेगी। बैठक में उपस्थित सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक मित्तल ने सुझाव दिया कि सुरक्षा प्रबंधों को चेक करने के लिए एएसएल आयोजित की जानी चाहिए ताकि नूंह और गुरुग्राम जिले पुलिस के अधिकारी आपसी तालमेल से बेहतर ढंग से काम कर सकें।

प्रदेश की ब्रांडिंग का काम होगा

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि आयोजन स्थल के अंदर और पूरे रूट पर ब्रांडिंग का काम किया जा रहा है। प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन स्थल पर एक स्टॉल भी लगाया जाएगा जिसमें हरियाणा सरकार की अनूठी पहलों तथा योजनाओं को वृत्तचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

पांच एएसएल एंबुलेंस रहेंगी तैनात

स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा ने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सुविधा से युक्त पांच एंबुलेंस भी आयोजन स्थल पर तैनात रहेंगी। आयोजन स्थल पर 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

अलग-अलग सड़क हादसों में दो की मौत

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक और मसूरी क्षेत्र में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में साइकिल से ड्यूटी जा रहे 40 वर्षीय अशोक कुमार को हाइड्रा ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। अशोक के भाई रामबीर सिंह ने केस दर्ज कराया है। दूसरा हादसा मसूरी क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है। एक्सप्रेसवे पार करते समय युवक के एक वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक वाहन के अगले हिस्से में फंस गया। करीब 100 मीटर तक घिसटने से उसकी मौत हो गई। युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी।

हापुड़ के हाफिजपुर के गांव मुरशदपुर निवासी रामबीर सिंह का कहना है कि उनके बड़े भाई अशोक कुमार गाजियाबाद में लालकुआं पर रहते थे। वह नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते थे। बुधवार सुबह करीब छह बजे वह साइकिल से ड्यूटी पर जा रहे थे। क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एनएच-9 के पास सार्थक पब्लिक स्कूल के सामने हाइड्रा ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। एसीपी वेव सिटी सलोनी अग्रवाल का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

एडीसीपी यातायात रामानंद कुशवाहा ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गांव रसूलपुर सिकरोड़ा के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि युवक पैदल सड़क पार कर रहा था। जबकि एक्सप्रेसवे पर पैदल सड़क पार करना प्रतिबंधित है। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। एसीपी मसूरी नरेश कुमार का कहना है कि मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष है। उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किए जा रहे हैं।

रकम दो गुना करने का लालच देकर महिला से तीन लाख ठगे

मोदीनगर। शातिर बदमाशों ने नगर की एक कॉलोनी निवासी महिला को ऑनलाइन टॉस्क पूरा करने पर रकम दो गुना करने का लालच देकर उससे तीन लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बैंक कॉलोनी निवासी सेफाली त्यागी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनके मोबाइल पर एक ऑनलाइन कंपनी का लिंक आया। लिंक क्लिक करने पर टॉस्क पूरा करने पर रकम दो गुना करने की जानकारी दी गई। सेफाली ने कथित कपंनी के नियानुसार काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान बदमाशों ने सेफाली को झांसे में लेकर उनके खाते से 3.17 लाख रुपये की ठगी कर ली। एसीपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

ब्लैकमेल करने पर युवक ने फंदा लगाकर दी जान

गाजियाबाद। संजयनगर सेक्टर-23 निवासी डिलीवरी बॉय अनुज (25) ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अनुज ने एक वीडियो बनाकर दोस्त को भेजा, जिसमें उसने शामली के परिवार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। अनुज की पत्नी सोनिया का आरोप है कि आरोपी उनके पति को ब्लैकमेल कर रकम की मांग कर रहे थे और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। अनुज मूलरूप से शामली का रहने वाला था। मामले में सोनिया ने युवती समेत छह लोगों के खिलाफ मधुबन बापूधाम थाने में केस दर्ज कराया है। शामली के गोशाला रोड निवासी सोनिया का कहना है कि उनके पति अनुज संजयनगर सेक्टर-23 में किराये के मकान में रहकर डिलीवरी बॉय की नौकरी करते थे। उनके पति जब भी शामली आते थे तो तनु बिड़ला, उनका भाई अनुज, मां, तनु की बड़ी बहन का देवर प्रिंस बिड़ला और मामा उन्हें ब्लैकमेल करते थे। लगातार मिल रही धमकियों से वह परेशान हो गए थे और तनाव में थे। 25 अगस्त को वह घर से गाजियाबाद के लिए चले गए और 29 अगस्त की रात करीब आठ बजे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुरानी रंजिश में किया हमला,पांच घायल

मोदीनगर। भोजपुर के कस्बा फरीदनगर में पुरानी रंजिश के चलते संघर्ष हो गया। दबंगों ने एक पक्ष पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में पांच लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। कस्बा फरीदनगर निवासी जाहिद और अब्बास के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों में बुधवार रात एक बार फिर संघर्ष हो गया। आरोप है कि अब्बास पक्ष ने जाहिद पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में जाहिद पक्ष के पांच लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। एसीपी ज्ञानप्रकाश का कहना है कि अब्बास, आसिफ, सुहैल व फइमुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

युवक के पैर में एक भाई ने चाकू मारा दूसरे ने सिर पर किया हमला

गाजियाबाद। वेव सिटी क्षेत्र में साइट पर काम खत्म करके घर लौट रहे राहुल यादव पर दो भाइयों ने तीन अज्ञात लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। एक ने राहुल के पैर में चाकू मारा तो दूसरे ने सिर पर हमला किया। हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में राहुल ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गांव दीनानाथपुर पूठी निवासी राहुल यादव का कहना है कि 21 अगस्त की शाम करीब सात बजे वह काम से घर लौट रहे थे। प्रताप फार्म के पास पूठी मोड़ पर पहुंचे तो शाहपुर बम्हैटा निवासी नवीन यादव अपने भाई मोनू यादव और तीन अन्य लोगों के साथ वहां वहां बैठा था। पांचों ने उन्हें रोककर मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर नवीन यादव ने उनके पैर में चाकू घोंप दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गए। इसके अलावा मोनू ने किसी भारी चीज से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गए। राहुल का कहना है कि मौके से गुजर रहे कुछ लोगों ने उनके घर पर सूचना दी तो परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों के आने पर आरोपी धमकी देकर फरार हो गए। एसीपी वेव सिटी सलोनी अग्रवाल का कहना है कि दो नामजद समेत तीन अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जी 20 समिट: एयरपोर्ट से यूपी गेट तक होगा मकान मालिक और दुकानदारों का सत्यापन

साहिबाबाद। दिल्ली में होने वाली जी 20 समिट से पहले ट्रांस हिंडन जोन की पुलिस हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से यूपी गेट तक सड़क के किनारे मकानों के लोग मालिक और दुकानदारों का सत्यापन करेगी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस सभी का ब्योरा अपने पास रखेगी। बृहस्तिवार शाम पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा ने मेहमानों के रूट और सुरक्षा प्लान निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त शाम को हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल पहुंचे। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश पी. कुमार डीसीपी ट्रांस हिंडन जोन और सहायक पुलिस उपायुक्त थे। उन्होंने सभी अधिकारियो के साथ बैठक की। इसमें एयरपोर्ट की आंतरिक सुरक्षा से लेकर विदेशी मेहमानों के आने का रूट प्लान व सुरक्षा नीति पर बात की। उन्होंने रूट पर सभी कट को बंद कर वहां यातायात पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। डीसीपी शुभम पटेल ने बताया कि मेहमानों को सिविल एयरपोर्ट से लेकर हिंडन एयरफोर्स होते हुए करहेड़ा वाया एलिवेटेड रोड से यूपी गेट और वहां से दिल्ली ले जाया जाएगा। 7 से 10 दिसंबर के बीच ट्रांस हिंडन जोन में विशेष सुरक्षा रहेगी। एयरपोर्ट से लेकर पूरे रूट पर सड़क किनारे किसी भी रेहडी-पटरी या दुकान नहीं लगने दी जाएगी।

नायब इमाम हत्या मामले में युवाओं की गिरफ्तारी के विरोध में सौंपा ज्ञापन

परिवहन विशेष न्यूज

महापंचायत कमेटी ने डीसीपी क्राइम के माध्यम से भेजा ज्ञापन कमेटी के सदस्यों ने सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप

गुरुग्राम। सेक्टर-57 स्थित निर्माणाधीन धार्मिक स्थल में आग लगाने और नायब इमाम की हत्या के मामले में चार युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में बृहस्पतिवार को कमेटी के सदस्यों ने डीसीपी क्राइम विजय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। कमेटी के सदस्यों ने बेगुनाह युवकों को फंसाने की बात कही है।

महापंचायत के बाद गठित कमेटी के सदस्यों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्दोष युवाओं से ज्यादती की जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि पुलिस गांव के निर्दोष युवाओं को बिना वजह तंग न करे। सरकार से आग्रह किया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे मगर निर्दोषों को रिहा करें। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने मामले को जल्द सुलझाने का अल्टीमेटम दिया।

सदस्यों ने कहा कि नूंह हिंसा में सरकार गुरुग्राम के लोगों को न्याय दिलाने में पूरी तरह फेल रही है। सदस्यों ने कहा कि वारदात के वक्त गिरफ्तार किए गए युवक वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस ने बगैर जांच किए ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 360 गांव झाड़सा खाप के प्रधान चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरान, पूर्व सरपंच वजीराबाद सूबे सिंह बोहरा, प्रधान अजीत, पूर्व पार्षद महेश दायमा, राजेंद्र, सोमदत्त शर्मा, फत्ते पहलवान, भूपेंद्र सिंह, तिगरा के पूर्व सरपंच अतर सिंह, यशवंत शेखावत, रोहताश बेदी एवं सतीश नागर आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि 31 जुलाई की देर रात सेक्टर-57 स्थित निर्माणाधीन मस्जिद को आग लगाने के बाद नायब इमाम मो. साद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने तिगरा के चार युवकों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच एसआइटी कर रही है।

महापंचायत में हेट स्पीच देने वाले को नोटिस

गुरुग्राम। सेक्टर-56 थाना पुलिस ने नायब इमाम की हत्या के बाद तिगरा में हुई महापंचायत के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महापंचायत के दौरान हेट स्पीच देने वालों की जांच चल रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कमेटी सदस्य कुलभूषण भारद्वाज को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए शुक्रवार दोपहर एक बजे बुलाया है।

सीएनजी भरने के बाद रुपये मांगने पर पंप कर्मियों पर हमला

गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाइवे स्थित सीएनजी पंप पर युवकों जम कर उत्पात मचाया। नखड़ोला गांव के निकट सीएनजी पंप पर बुधवार रात 12:30 बजे कार सवार युवकों ने पहले 600 रुपये की सीएनजी भरवाई और रुपये मांगने पर पंप कर्मियों के साथ लाठी, डंडों से पिटाई कर दी। इसमें तीन पंप कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि एक अन्य को भी चोटें आई हैं। वहीं दो आरोपी युवकों को पंप कर्मियों ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। दोनों आरोपियों की पहचान मानेसर के प्रवेश और नवीन के रूप में हुई। आरोपियों की संख्या सात से आठ बताई जा रही है, जिनकी पहचान कर ली गई है। नखड़ोला गांव के निकट इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। जिस पर सीएनजी भी मिलती है। बुधवार रात 12:30 बजे एक गाड़ी में युवक सीएनजी भरवाने के लिए पहुंचे। पंप कर्मियों ने सीएनजी भरने से पहले सभी को गाड़ी से बाहर आने को कहा तो नशे में धुत कई युवकों ने बाहर आने से मना कर दिया, लेकिन नियम के बारे में बताकर सभी को निकाला। कर्मियों ने गाड़ी में सीएनजी भरने के बाद 600 रुपये मांगे तो युवकों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इस बीच पंप कर्मियों ने मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे, लेकिन नशे में धुत आरोपियों ने कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं हमलावरों ने डंडों से पंप कर्मियों के सिर पर वार करने शुरू कर दिए। जिससे तीन पंप कर्मी बेहोश हो गए, लेकिन युवकों ने मारपीट बंद नहीं की। करीब 20 मिनट तक यह मारपीट जारी रखी। इस दौरान एक पंप कर्मी ने आरोपियों को भगाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर से धुआं भी किया लेकिन युवकों ने उसे भी बुरी तरह पीटा। इसके बाद आरोपी भाग निकले। मामले में दो युवकों को पंप कर्मियों ने पकड़ लिया और कुछ ही देर बाद पहुंची पुलिस को सौंप दिया। खेड़की दौला थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि पंप पर कार्यरत कृष्ण, आकाश, बिजू व सुखबीर घायल हुए हैं। जो प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराए गए हैं। इनमें से कृष्ण, आकाश व बिजू को गंभीर चोटें लगने के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की पहचान मानेसर निवासियों के रूप में हुई है। जबकि एक पटौदी का रहने वाला है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंप संचालक का आरोप है कि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है। उस हिसाब से नहीं लगता कि गुरुग्राम में कोई 600 रुपये के लिए इतना विवाद करेगा। पहले तो कार से आरोपी उतर नहीं रहे थे, जब उतरे तो कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

एसीपी ने भाई बनकर बचाई 10वीं की छात्रा की जान

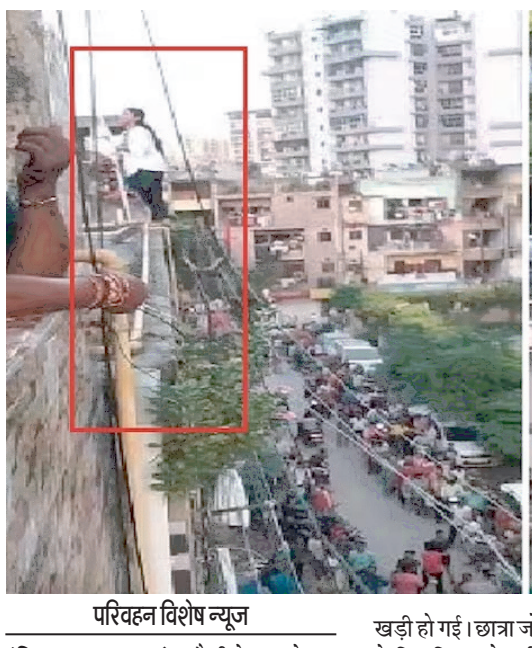

परिवहन विशेष न्यूज

इंदिरापुरम। अभयखंड चौकी के सामने बृहस्पतिवार शाम पौने छह बजे 10वीं की छात्रा पिता की डांट से नाराज होकर आत्महत्या करने के लिए चौथी मंजिल पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। लोगों ने करीब डेढ़ घंटे तक उसे समझाने का प्रयास किया। एसीपी स्वतंत्र सिंह, पुलिस, अग्निशमन टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसीपी ने छात्रा का भाई बनकर बात उसकी सुनी और उसे सकुशल नीचे उतारा।

दिल्ली के एक स्कूल की छात्रा की मां का पिछले महीने देहांत हो गया था। घर में पिता और अन्य सदस्य हैं। बृहस्पतिवार को छात्रा घर में थी। तभी पिता ने उसे पढ़ाई के लिए डांट लगा दी। इससे क्षुब्ध होकर वह बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर चढ़ गई और पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल पर जाकर खड़ी हो गई। छात्रा जोर-जोर से आत्महत्या के लिए चिल्लाने लगी। लोगों ने उसे देखकर शोर मचाया और बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बीच उसने किसी को भी पास आने पर कूदने की धमकी दी। बिल्डिंग के सामने अभयखंड चौकी की पुलिस ने उसे देखा और बचाने के लिए दौड़े। छात्रा ने कई बार कूदने का प्रयास किया लेकिन लोगों ने रोक लिया। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी योगेंद्र सिंह ने छात्रा से बात की लेकिन वह बात करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने रक्षाबंधन पर छात्रा को उसका बड़ा भाई बताते हुए राखी बांधने को कहा। साथ ही हर समस्याओं सुलझाने की बात कही। नीचे उतरने के बाद वह बेहोश हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

करीब दो घंटे तक चला ड्रामा

शाम करीब पौने छह बजे छात्रा को छत पर आत्महत्या का प्रयास करते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे। पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम भी छात्रा को बचाने में जुटी थी। एसीपी ने छात्रा को कई बार खुद को उसका भाई बताकर विश्वास में लिया। फिर जब उन्होंने बड़ा भाई बनकर राखी बांधने के लिए बुलाया तो वह मान गई।

कोट

एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि छात्रा को सकुशल नीचे उतार लिया है। वह घरेलू बात से परेशान थी। उसकी मां का 18 तारीख को देहांत हो गया था। छात्रा का भाई बनकर उसे समझाया था। बेहोश होने पर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया।

कलेक्शन एजेंट पर 20 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

इंदिरापुरम। कोतवाली पुलिस को एक कंपनी के निदेशक ने कर्मचारी पर 20 लाख रुपये हड़पने का मुकदमा कराया है। कर्मचारी पर पांच लाख रुपये नकद और अन्य ग्राहकों को लोन देने के बहाने 15 लाख रुपये लेने का आरोप है। पैसे मांगने पर कर्मचारी आत्महत्या की धमकी दे रहा है। निदेशक रोहित अग्रवाल का कहना है कि कंपनी लोगों को 10 से 30 हजार रुपये तक का लोन देती है। कंपनी में डासना के इंद्रगढ़ी निवासी महेश तोमर कलेक्शन एजेंट है। उनका आरोप है कि कुछ समय पहले महेश ने निजी काम के लिए पांच लाख रुपये नकद लिए थे। उसके बाद ग्राहकों को लोन देने के लिए 15 लाख रुपये लिए थे लेकिन उसने किसी को लोन नहीं दिया। जांच में शक होने पर उससे पूछताछ हुई तो वह रुपये को लेकर बहाने बनाने लगा। उससे रुपये लौटाने के लिए कहा गया तो वह आत्महत्या कर केस में फंसाने की धमकी देने लगा। उन्होंने शिकायत के साथ पुलिस को एजेंट की धमकी वाली ऑडियो भी दी है। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि शिकायत पर मुकदमा किया है। उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

200 रुपये चोरी के आरोप में डांटा, तो किशोर घर से भागा

लोनी। कोतवाली क्षेत्र के प्रशांत विहार कॉलोनी में रहने वाला 11 वर्षीय किशोर 200 रुपये चोरी के आरोप लगने के बाद घर से भाग गया था। मकान मालिक ने किशोर को डांटा था। चार दिनों बाद बृहस्पतिवार को पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर उसे बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया। किशोर घर से निकलकर सड़क किनारे रह रहा था। किशोर के पिता की कुछ समय पूर्व मौत हो गई थी। परिवार में मां और बहनें हैं। मां प्रशांत विहार कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में बच्चों के साथ रहती हैं। शुक्रवार को मकान मालिक ने किशोर को 200 रुपये चोरी करने के आरोप में डांट दिया था। इसके बाद किशोर घर से कहीं चला गया था। परिजनों ने किशोर को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों के घर जाकर तलाश किया। दोस्तों से भी पूछा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर किशोर को बरामद करने की मांग की। एसीपी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि किशोर की बरामदगी के लिए पुलिस ने घर से लेकर आसपास क्षेत्र के अलग-अलग 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। बुधवार तक किशोर लोनी दो नंबर के पास दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम दो नंबर इलाके पर रुकी। पुलिस ने किशोर को बरामद कर लिया। बरामद किशोर ने बताया कि वह सड़क किनारे रात के समय सोता था।

लिव-इन रिलेशन में मिली मौत: लटका मिला युवती का शव

परिवहन विशेष न्यूज

पुलिस ने महिला को नीचे उतरकर कमरे में जांच की। घटना की सूचना मिलने पर परिवार के लोग कौशांबी थाने पर पहुंचे हैं।

गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली में गुरुवार देर रात कमरे में 23 साल की जिम रिसेप्शनिस्ट का पंखे से शव लटका मिला। वह गाजीपुर के युवक के साथ रिलेशनशिप में रहती थी। घटना के बाद आरोपी कैमरा बंद कर भाग गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर थाने के बाहर शव रख कर हंगामा किया। पुलिस ने समझाकर शव अंतिम संस्कार के लिए भेजा। वैशाली में रहने वाली युवती जिम में रिसेप्शनिस्ट थी। वहां दिल्ली गाजीपुर के युवक से उसकी जान पहचान हो गई थी। दोनों 4 साल से वैशाली में एक साथ किराए के कमरे में रहते थे। गुरुवार रात दोनों साथ में थे। इस बीच युवक कमरे को बंद कर बाहर चला गया। देर रात में पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। कमरे में युवती पंखे से लटकी हुई थी।

घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया। मौके से एक डायरी और युवती का फोन मिला है। सूचना पर पहुंचे परिवार के लोगों ने आरोपी युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। उसके बाद थाने पहुंच कर पुलिस को युवक के खिलाफ युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दी। कौशांबी पुलिस ने यूपी के भाई की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर भागे युवक की तलाश शुरू कर दी।

थाने के बाहर शव रखकर की सड़क जाम

पोस्टमार्टम के बाद परिजन युवती का शव लेकर कौशांबी थाने पहुंचे। मां पिता और अन्य लोगों ने कौशांबी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। मां का कहना था कि उनकी बेटी वापस घर आना चाहती थी लेकिन युवक ने धमकी देकर उसे नहीं जाने दिया। करीब ढाई घंटे तक परिजन थाने के बाहर डटे रहे। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह और थानाध्यक्ष अंकित तरार ने परिजनों को समझ कर शव अंतिम संस्कार के लिए भेजा।

एसीपी स्वतंत्र सिंह का कहना है कि मामले में यूपी के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

अमेरिकी प्रशासन की वाहन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं को 12 अरब डॉलर की पेशकश, ईवी-एडवांस्ड वाहनों को बढ़ावा

अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ऑटो निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को इलेक्ट्रिक और अन्य एडवांस्ड वाहनों के उत्पादन के लिए अपने मैन्युफेक्चरिंग प्लांट को फिर से बनाने के लिए 12 अरब डॉलर के अनुदान और लोन की पेशकश कर रहा है। ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

कार-मैन्युफेक्चरिंग राज्य मिशिगन के पूर्व गवर्नर ग्रैनहोम ने एक कॉल में संवाददाताओं से कहा, ₹जब हम ईवी में बदलाव कर रहे हैं, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि श्रमिक भी आसानी से इसे अपना सकें, कि कोई श्रमिक, कोई समुदाय छूट न जाए।

इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए मौजूदा ऑटो प्लांटों के कंवर्जन के लिए अनुदान और अन्य सब्सिडी में तेजी लाने से व्हाइट हाउस को ईवी युग की शुरुआत में मदद करने के मकसद से प्रस्तावित पर्यावरण नियमों पर वाहन निर्माताओं और यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स (यूएडब्ल्यू) यूनियन की आलोचना को कम करने में मदद मिल सकती है।

यूएडब्ल्यू ने चेतावनी दी है कि तेजी से बदलाव से मिशिगन, ओहियो, इलिनोइस और इंडियाना जैसे राज्यों में हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।

पिछले हफ्ते यूएडब्ल्यू के सदस्यों ने डेट्रॉइट थ्री वाहन निर्माताओं के यहां हड़ताल को अधिकृत करने के पक्ष में भारी मतदान किया। यदि मौजूदा चार साल का अनुबंध 14 सितंबर को खत्म होने से पहले वेतन और पेंशन योजनाओं पर समझौता नहीं होता है।

गुरुवार को यूएडब्ल्यू के अध्यक्ष शॉन फेन ने घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि नीति ₹नियोक्ताओं को स्पष्ट करती है कि ईवी परिवर्तन में उच्च वेतन और सुरक्षा मानकों के साथ मजबूत यूनियन भागीदारी शामिल होनी चाहिए, जिसके लिए यूएडब्ल्यू सदस्यों की पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है।₹

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक रिलीज में कहा कि ₹स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था का निर्माण उन ऑटो कंपनियों और यूनियनकृत श्रमिकों के लिए एक जीत का मौका दे सकता है और देना चाहिए जिन्होंने दशकों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है।₹

फेन ने इलिनोइस के बेल्वीडेरे में एक जीप फैक्ट्री को बचाने की कसम खाई है, जिसे स्टेलंटिस बंद करने की राह पर रखा है। ऑटोमेकर ने यह संभावना खुली रखी है कि फैक्ट्री को सरकारी सहायता से एक नया उत्पाद मिल सकता है।

विज्ञापन

जब उनसे इस संभावना के बारे में पूछा गया कि अनुदान उस कारखाने को खुला रख सकता है, तो ग्रैनहोम ने कहा कि जो प्लांट समुदायों के आसपास बनाए गए थे, वे ₹इन फंडिंग अवसरों का लाभ उठाने में प्रमुख हैं।

ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने कॉल पर कहा कि कंपनियों को फंडिंग हासिल करने के लिए कोई विशिष्ट श्रम आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जिन परियोजनाओं में श्रम की स्थिति बेहतर होगी, उन्हें फंडिंग हासिल करने की ज्यादा संभावना होगी।

ईवी ने कुछ हद तक कम किया प्रदूषण, फिर भी पेट्रोल डीजल के वाहनों से प्रदूषण अधिक

बिलासपुर। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानि ईवी की संख्या लगातार बढ़ने के बाद शहर में बढ़ते प्रदूषण में कुछ कमी आई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दो पहिया, चार पहिया और भारी वाहन लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं। इससे लगातार पर्यावरण में जहर घुल रहा है। शहर में ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने अब तक कोई प्रयास नहीं किए है। एकमात्र ईवी चार्जिंग स्टेशन है और शहर में ई रिक्शा की संख्या 1200 के पार है।

केन्द्र सरकार ने बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी में वर्ष 2018 में शामिल किया था। स्मार्ट सिटी में चलने वाले सवारी वाहनों में ईवी को प्राथमिकता दी गई थी। शहर में इन वाहनों के चलने से डीजल और पेट्रोल वाहनों के चले के कारण होने वाले प्रदूषण से भी निजात मिल सकती है। खासकर ऐसे वाहन जिनकी प्रदूषण जांच नहीं होती । उनसे लगातार कार्बन डॉई आक्साइड निकल रहा है। इससे प्रदूषण में जहर घुल रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। खासकर इससे दमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

बदलने पर जोर नहीं

स्मार्ट सिटी को कार्बन फ्री रखने के लकड़ी और कोयले का उपयोग होने वाले कारखानों पर रोक लगाना जरूरी है। इसके साथ ही सड़क पर दिनभर दौड़ने वाले डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को विशेष तौर पर लोडिंग रिक्शा को भी ई व्हीकल में बदलने की पहल की जानी थी, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन ने अब तक पहल नहीं की है।

एकमात्र ई रिक्शा चार्जिंग पाइंट

ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने खानापूर्ति ही की है। पं. श्यामलाल चर्तुवेदी स्मार्ट रोड पर एकमात्र ई-रिक्शा चार्जिंग पाइंट लगाया गया है। इसमें एक बार में सिर्फ 6 ई रिक्शा चार्ज हो सकते हैं, जबकि शहर में ई रिक्शा की संख्या 1200 से अधिक है।।

कार्बन डाई आक्साइड में थोड़ी कमी

शहर में लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को शहर का एक्यूआई 82 रहा और इसमें पीएम 10- 94, पीएम 2.5- 22, कार्बन- 2260 और एनओ-2 - रहा। वहीं 6 महीने पहले शहर में कार्बन की मात्रा 2300 से अधिक था।

शहर में ई व्हीकल की स्थित

टू व्हीलर- 215
थ्री व्हीलर गुड्स - 40
ई-रिक्शा - 1290
मोटर कैब- 12
मोटर कार- 125
मोपेड- 73
मोटर साइकिल स्कूटर- 3590
गुड्स कैरियर- 6

पहला ई रिक्शा चार्जिंग पाइंट हुआ ध्वस्त

नगर निगम ने 10 वर्ष पूर्व सरकंडा स्थित आदिम जाति कल्याण थाना में ई रिक्शा चार्जिंग पाइंट बनाया था। यहां 12 ई रिक्शा एक बार में चार्ज होते थे, लेकिन इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान में यह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है।

ई रिक्शा और अन्य ईवी चलने से शहर के प्रदूषण में कमी आई है। इसे बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहर के अलग-अलग 8 स्थानों पर ई रिक्शा चार्जिंग पाइंट बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है। ई रिक्शा का व्यावसायिक उपयोग होता है इसलिए उनसे चार्जिंग के लिए शुल्क भी लिया जाएगा।

बिलासपुर शहर में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। हम औद्योगिक इकाई एवं वाहन से निकलने वाले काले धुएं को इसका जिम्मेदार मान सकते हैं। पर्यावरण में कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अतिरिक्त मात्रा प्रदूषण का मुख्य कारण है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। बिलासपुर सहर में ईवी बैटरी से संचलित होने वाले ऑटोरिक्शा, चार पहिया वाहन, दुपहिया वहां की संख्या दिनो दिन बढ़ रही है जो कुछ हद तक प्रदूषण पर लग सकती है, मगर साथ ही पुराने वाहन जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उनकी भी संख्या कुछ काम नहीं है जो लगतार काला धुआ छोड़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसर, सहार के नेहरू चौक, मंगला चौक, महाराणा प्रताप चौक एवं स्टेशन चौराहा पर अधिकार समय कार्बन मोनो ऑक्साइड अपने मानक स्टार 120 पीपीएम से ज्यादा ही रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड ईवम नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा भी 0.0007 पीपीएम ईवम 1500 पीपीएम से ज्यादा ही मापी गई है। जिसे तो स्पष्ट है कि अभी ईवी बाड़ियों से परिवर्तन कई फायदे होने वाले हैं।

ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मॉडल को अपनाना चाहिए। वहां चार्जिंग स्टेशन के बजाए बैटरी स्टेशन बने हैं, जहां कोई भी बैटरी को किराए पर लेकर अपने वाहन चला सकता है। इससे उसे खर्च भी कम आता है और वाहनों को खड़े भी नहीं रहना पड़ता है। ये सिस्टम ज्यादा मददगार होगा।

EV उद्योग को बढ़ावा देने के लिए RIL लगाएगी LFP बैटरी फैक्ट्री

भारत में ईवी बिक्री में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसी प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियां कई वर्षों से एलएफपी प्रौद्योगिकी पर काम कर रही हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2026 तक लीथियम फेरस फॉस्फेट (एलएफपी) प्रौद्योगिकी के साथ बैटरी रसायन, सेल और पैक निर्माण के लिए विशाल बैटरी फैक्टरी स्थापित कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग को लीथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट (एलआई-एनएमसी) की मौजूदा बैटरी तकनीक से उभरती एलएफपी बैटरी तकनीक की दिशा में बढ़ने के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

यूबीएस के अनुमान के मुताबिक एलएफपी बैटरी द्वारा संचालित वैश्विक ईवी वर्ष 2030 तक वैश्विक बाजार का 40 प्रतिशत हिस्सा हो सकते हैं, जबकि फिलहाल यह अनुमान 17 प्रतिशत है। टेस्ला, रिवियन और फोर्ड जैसी कंपनियां इस प्रौद्योगिकी पर बड़ा दांव लगा रही हैं।

भारत में ईवी बिक्री में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसी प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियां कई वर्षों से एलएफपी प्रौद्योगिकी पर काम कर रही हैं। दिल्ली की ओकाया इलेक्ट्रिक पहले ही स्कूटर क्षेत्र में अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों के मुकाबले विपणन के प्रमुख अंतर वाले कारक के रूप में एलएफपी बैटरी का उपयोग करने वाली पहली कंपनी बन गई है।

यात्री कारों में टाटा मोटर्स अपनी सभी इलेक्ट्रिक कारों – नेक्सन, टिगोर और टियागो में एलएफपी बैटरी का इस्तेमाल कर रही है। सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माताओं की बैटरी भारत में टाटा ऑटोकॉम्प द्वारा असेंबल की जाती है, जिसका चीन की कंपनी गुओक्सुआन हाई-टेक के साथ संयुक्त उद्यम है। इसका एक उदाहरण एमजी मोटर्स है, जिसने हाल ही में अपना किफायती मॉडल कॉमेट पेश किया है।

बैटरी कंपनियां दोनों तरह की बैटरी बनाने के लिए कतारबद्ध हो रही हैं। इनमें चीन की एसवीओएलटी की प्रौद्योगिकी के साथ एक्साइड, अमर राजा और पैनासोनिक जैसे कुछ नाम शामिल हैं। एलएफपी बैटरियों के कुछ फायदे होते हैं। उनका निर्माण सस्ता होता है, उन्हें निकल (जिसकी कीमत यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद बढ़ गई है, जो इसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता है) की आवश्यकता नहीं होती है और न ही कोबाल्ट (यह मुख्य रूप से कांगो में उपलब्ध है, जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन मसला बना हुआ है) की जरूरत होती है।

दरअसल एलएफपी कैथोड को केवल आयरन और फॉस्फेट की ही आवश्यकता होती है, जो दुनिया भर और भारत में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनकी दाम भी स्थिर हैं। एथर एनर्जी के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी तरुण मेहता ने कहा 'एलएफपी सस्ता और सुरक्षित है तथा हम इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं।'

ग्राहकों के नजरिये से भी एलएफपी बैटरियां अधिक सुरक्षित हैं और लंबे वक्त तक साथ देती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में सबसे पहले बैटरी का उपयोग करने वाली ओकाया इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्याधिकारी अंशुल गुप्ता ने कहा कि बड़ा अंतर सुरक्षा का है। बैटरी धुआं छोड़ेगी, लेकिन स्कूटर में आग नहीं लगेगी या विस्फोट नहीं होगा। बैटरी का जीवनचक्र एनएमसी बैटरी से कम से कम दोगुना (सात से 10 वर्ष) रहता है।

एलएफपी बैटरियां एनएमसी बैटरियों की तुलना में पर्यावरण के अधिक अनुकूल होती हैं क्योंकि उनके निपटान के वक्त कोबाल्ट के पर्यावरण में जाने की कोई चिंता नहीं होती है। इनका दूसरा पहलू यह है कि एलएफपी बैटरियों को भंडारण के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है (हालांकि इस समस्या को हल करने के लिए डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है) और उनमें ऊर्जा की सघनता कम होती है। इसका मतलब यह है कि एक बार के चार्ज में इनकी रेंज काफी कम होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए शायद इससे कोई समस्या न हो, लेकिन यात्री कारों के लिए निश्चित रूप से होगी।

किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप तो कोई जमानत पर घूम रहा, ऐसे नेताओं वाला गठबंधन कैसे ईमानदार सरकार दे पायेगा?

नीरज कुमार दुबे

इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता और गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हासिल करने के सबसे बड़े इच्छुक राहुल गांधी खुद ही कई मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। यहां तक कि वह अपने पारिवारिक गढ़ अमेठी से अपना पिछला लोकसभा चुनाव तक हार चुके हैं।

विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक से पहले ही जिस तरह इसके घटक दलों की ओर से अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने की मांग की जा रही है वह जरा भी आश्चर्यजनक दृश्य नहीं है। दरअसल विपक्षी गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी चाहते हैं तो कुछ की चाह इस गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनने की है। कुल मिलाकर देखा जाये तो स्थिति एक अनार सौ बीमार वाली है। सवाल उठता है कि जब नेतृत्व को लेकर ही इतना झगड़ा है तो सीटों के बँटवारे जैसे सबसे मुश्किल काम को कैसे अंजाम दिया जायेगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की पिछली बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दे चुके हैं इसलिए सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जवाब ढूंढ़ने के लिए जरा इस गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के नामों पर नजर घुमाएंगे तो पाएंगे कि इनमें कई ऐसे हैं जो घोटाले या अन्य मामलों का सामना कर रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जोकि जमानत पर बाहर चल रहे हैं। मंच पर बैठे नेताओं की तस्वीरें देखते जाइये और उनसे जुड़े मामलों के बारे में सर्च करते जाइये आपको पता चल जायेगा कि यह सब क्यों एकत्रित हुए हैं। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता और गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हासिल करने के सबसे बड़े इच्छुक राहुल गांधी खुद ही कई मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। यहां तक कि वह अपने पारिवारिक गढ़ अमेठी से अपना पिछला लोकसभा चुनाव तक हार चुके हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिनको उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाये जाने की मांग कर रही है, उनके बारे में यह जान लेना बहुत जरूरी है कि वह राज्य में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मात्र दो दिन अपने कार्यालय गये थे। अपने पिता की ओर से स्थापित राजनीतिक सिद्धांतों को उन्होंने तिलांजलि देकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाई थी और हिंदुत्व के मुद्दे को किनारे रख दिया था। वह मुख्यमंत्री के रूप में कितने सक्षम थे इसका अंदाजा तब भी लग गया था जब उनको कानों कान खबर नहीं लगी थी और एकनाथ शिंदे पार्टी और सरकार उनसे झटक लेने में सफल रहे थे। इसके अलावा उनकी सरकार पर कोरोना काल में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे।

प्रधानमंत्री पद का सपना वर्षों से अपने मन में संजोए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को जनता कैसे स्वीकार कर सकती है जिसने लगभग दो दशकों के अपने शासन के बावजूद अपने राज्य को हर मायने में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बनाये रखा। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति पर आखिर जनता कैसे भरोसा कर सकती है जो अपने फायदे को देखते हुए समय-समय पर गठबंधन ही बदलते रहते हैं?

प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए लालायित नेताओं में अरविंद केजरीवाल की बात करें तो आपको याद दिला दें कि उनकी सरकार पर तो भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप हैं कि उनके उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया छह महीने से जेल में बंद हैं तथा एक और मंत्री की भ्रष्टाचार मामले में साल भर से ज्यादा समय बाद जमानत हुई वह भी खराब स्वास्थ्य के चलते। दिल्ली के मुख्यमंत्री राज्य के उपराज्यपाल के साथ जिस तरह का रुख रखते हैं उसका सीधा असर प्रशासन पर पड़ता है जिसका खामियाजा आखिरकार जनता को ही उठाना पड़ता है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री पद की एक और उम्मीदवार ममता बनर्जी की बात करें तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और प्रशासन की क्या स्थिति है यह किसी से छिपा नहीं है। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। खुद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे हैं। ममता दीदी के राज में मंत्री और उनकी गर्ल फ्रैंड के घर से नोटों के ऐसे पहाड़ मिले थे जिसके चर्चे पूरी दुनिया में रहे थे। अदालतें तक कई बार पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी हैं।

प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हासिल करने के नये इच्छुक अखिलेश यादव की बात करें तो उनके बारे में तो उनके पिताजी ही कह कर गये हैं कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वह दूसरों का क्या होगा। अखिलेश यादव को लगातार दो चुनावों से उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री पद के लायक भी नहीं समझा ऐसे में सवाल उठता है कि वह खुद में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी कैसे देख रहे हैं?

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी हासिल करने के तो आकांक्षी नहीं लग रहे लेकिन उनके गठबंधन में बने रहने का कारण खुद को बचाने की कवायद ही समझ आता है। यह सर्वविदित है कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार से जुड़े कई लोगों के खिलाफ मामले चल रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी भ्रष्टाचार के तमाम मामलों से घिरे हुए हैं और लगातार जमानत पर चल रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री भी जिस तरह भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जा रहे हैं उससे भी यही लगता है कि भ्रष्टाचार के मामलों से घिरीं सारी पार्टियों के नेता एक मंच पर इसलिए जुट रहे हैं ताकि अपनी शक्ति बढ़ाकर वह बच सकें। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर से फारुख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का अब कोई आधार नहीं बचा है इसलिए वह विपक्षी मंच पर जुट रहे हैं ताकि अपना राजनीतिक वजूद बचाये रखा जा सके।

जहां तक शरद पवार की बात है तो अब वह सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक ही रह गये हैं क्योंकि पार्टी पर तो उनके भतीजे अजित पवार का कब्जा हो चुका है। पवार कहने को इंडिया गठबंधन के मंच पर हैं लेकिन उनकी राजनीति पलटी मारते रहने की रही है। बहरहाल, अब जनता को तय करना है कि तेजी से आगे बढ़ती दुनिया के साथ कदमताल करने और उससे आगे निकलने के लिए हमें खिचड़ी सरकार की जरूरत है या फिर कड़े और बड़े निर्णय लेने वाली स्पष्ट बहुमत वाली सरकार की?

संपादक की कलम से

परिवहन का रुख बदलना होगा

नक्शे पे पहली बार हिमाचल ने जख्म भर लिए, धरती के दर्द ने कुछ नए रास्ते चुन लिए। कीरतपुर-मनाली फोरलेन से गुजरने की सजा भुगतते पंडोह बांध के करीब का कैंची मोड़, इस सफर की कवायद को अस्थिर बना देता है। कभी लगा कि कीरतपुर से मनाली के बीच उभरा यह फॉल्ट, सदियों के दोष को माथे मढ़ गया, लेकिन फिर विकास का ख्वाब जिंदा निकला। वहीं जहां सडक़ के आंसू निकले थे, एक नई आशा का पहाड़ खड़ा हो गया। एनएचएआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव की मानें, तो कुल्लू दशहरा के मेहमान इसी रास्ते से पहुंचेंगे। अक्तूबर तक फोरलेन पुनः खुद के घाव भर लेगी, लेकिन आपदा के मुआयने ने सडक़ निर्माण की विधा को कई हिदायतें और कई विकल्प तराशने की जरूरत बता दी। जाहिर है फोरलेन निर्माण की गति और पहाड़ पर सडक़ बनाने की मति में कुछ तो सुधार आएगा, ताकि आइंदा बारिशों से घाव की सतह हमारे विकास की कलह न बने। बेशक एनएचएआई ने अपनी प्राथमिकताओं में शुरू की गई तमाम परियोजनाओं की सुध लेते हुए इन्हें वक्त रहते सुधारने की गुंजाइश को पूरा करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसी के साथ प्रदेश के लिए आपदा के बाद विकास की अगली सदी को संबोधित करने की हिदायतें बदली हैं।

इन्हीं के प्रारूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय एजेंसी को अपना प्रारूप बदलने की गुजारिश की है। हिमाचल ने परिवहन का रुख बदलने के लिए तीन ऐसी सुरंगें चुनी हैं, जिनके मार्फत सफर का नक्शा बदलेगा। भुभु जोत, चंबा-चुवाड़ी और भावा से पिन घाटी को जोडने वाली सुरंगों का निर्माण अगर प्राथमिक आधार पर होता है, तो हिमाचल आज जहां खड़ा है, वहां से कहीं आगे सुरक्षित, सदाबहार और नए तरानों के साथ अपनी पेशकश कर सकता है। चंबा से चुवाड़ी और घटासनी से भुभुजोत सुरंगों के दायरे में दूरियां घटेंगी और साथ ही पर्यटन का एहसास भी बदलेगा। जाहिर है ये दो सुरंगें कहीं न कहीं कांगड़ा के केंद्र में अन्य जिलों से हाथ मिला सकती हैं। भुभुजोत अगर कांगड़ा-मनाली के बीच 55 किलोमीटर सफर घटा रही है, तो चंबा-चुवाड़ी सुरंग से पूरा भूगोल बदल सकता है। सुरंग रास्तों के कई और प्रस्ताव भी सामने आते रहे हैं, लेकिन न योजनाएं बनीं और न ही राज्य की प्राथमिकताएं तय हुईं।

दरअसल हिमाचल के विकास की दृष्टि से चार संसदीय क्षेत्रों में राजनीतिक हसरतें परवान चढ़ती गईं, नतीजतन औद्योगिक विकास के सारे मुहावरे परवाणू के बाद बीबीएन में सिमट गए। फोरलेन की पैमाइश परवाणू-शिमला व कीरतपुर-मनाली तक होती रही, जबकि आठ जिलों की जनता को ढोने वाले मटौर-शिमला ऐसी किसी प्राथमिकता में बहुत देरी से आ रहा है। इसी तरह ऊना रेल की परिधि में अगर मंदिर पर्यटन का खाका बनता तो अब तक अंब-अंदौरा से चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, कांगड़ा, चामुंडा, दियोटसिद्ध तथा नयनादेवी तक पटरियों का विस्तार हो जाता। अंब-अंदौरा से मात्र पचास किलोमीटर का सफर ज्वालाजी को हिमाचल में रेल विस्तार का प्रमुख केंद्र बना सकता है। इसी तरह अगर सरकार जल परिवहन पर गंभीरता से विचार करें तो कौल डैम के मार्फत तत्तापानी, गोविंदसागर के मार्फत बिलासपुर से पंजाब तथा पौंग बांध के मार्फत कांगड़ा-हमीरपुर के बीच पर्यटन के कई टापू खड़े कर सकते हैं। दरअसल हिमाचल की महत्त्वाकांक्षा अलग-अलग प्रदेश सरकारों तथा केंद्र सरकारों के बीच बिखरती रही है। ढंग से माल ढुलाई पर ही गौर करते, तो अब तक सेब की ढुलाई के लिए रज्जु मार्गों की एक श्रृंखला बन चुकी होती। हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए स्थायी नीतियों, राजनीतिक सौहार्द, फिजूलखर्ची पर रोक तथा क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर समूचे प्रदेश के नक्शे पर क्रांतिकारी उद्घोष को जिंदा रखना होगा।

राय

महंगाई, बेकारी का चुनाव

चुनावी मौसम छाने लगा है, तो महंगाई और बेरोजगारी दरों की गर्मागर्म चर्चा छिड़ी है। कुछ सर्वे सामने आए हैं, जिनमें औसतन 25 फीसदी लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता और सरोकार जताए हैं। ये आम चुनाव 2024 के प्रमुख मुद्दे बनेंगे अथवा नहीं, उसके मद्देनजर कुछ इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों के जनादेश क्या होंगे, उनसे भी बहुत कुछ स्पष्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया है। देश के निम्न-मध्य वर्ग के लिए 903 रुपए का सिलेंडर भी महंगा है। सिलेंडर उपभोक्ताओं की कुल संख्या 31.4 करोड़ है, जिसमें 10.35 करोड़ 'उज्ज्वला योजना' के लाभार्थी हैं। उन्हें गैस सिलेंडर 700 रुपए का मिलेगा। बुनियादी सवाल महंगाई का है, जिसकी जुलाई में खुदरा दर 7.44 फीसदी थी। यह बीते 15 माह के रिकॉर्ड स्तर पर थी। जुलाई में ही उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति की दर 11.5 फीसदी थी। मुद्रास्फीति की उच्चतम दर मोदी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने तय कर रखी थी कि वह 6 फीसदी से नीचे ही रहनी चाहिए। सरकार उसमें लगभग सफल रही थी, लेकिन अब हदें लांघ दी गई हैं, तो सरकार भी चिंतित लग रही है। महंगाई का असर चौतरफा होता है। चूंकि अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, तो बेरोजगारी दर 7.9 फीसदी भी चुभती है। यह दर अमरीका, ब्रिटेन, चीन, जापान और जर्मनी आदि बड़े देशों की बेकारी दर से अधिक है। अब मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल को कुछ सस्ता करने पर विचार कर रही है।

केंद्र सरकार आधा दर्जन बार उत्पाद शुल्क बढ़ा कर 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देशवासियों से वसूल चुकी है। तेल-गैस कंपनियों ने भी करीब 35,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कूट लिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब 86 डॉलर प्रति बैरल है। रूस से अपेक्षाकृत सस्ता तेल आयात किया जा रहा है, लेकिन आम उपभोक्ता को महंगा पेट्रोल-डीजल खरीदना पड़ रहा है। वह राज्यों की अर्थव्यवस्था का भी बुनियादी स्रोत है, लिहाजा राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना सरीखे राज्यों में सर्वाधिक महंगाई है। फिर भी राज्य सरकारें 'रेवड़ी' बांटने में जुटी हैं, क्योंकि वोट चाहिए। चूंकि पांच राज्यों के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मोदी सरकार भी नहीं चाहेगी कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा बने, जो चुनावों को प्रभावित कर सके। नतीजतन महंगाई पर मंथन जारी है। देशवासियों को और भी राहतें दी जा सकती हैं। बेशक अब टमाटर बाजार में सस्ता हो गया है, लेकिन वह करीब 1400 फीसदी तक महंगा हुआ था। जमाखोरों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। सब्जियां अब भी औसतन 37 फीसदी महंगी हैं। यदि बेरोजगारी की दर की बात करें, तो बीते 14 माह में, रोजगार मेलों के जरिए, करीब 5.5 लाख नियुक्ति-पत्र ही बांटे गए हैं। 2014-22 के दौरान 22.05 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन 7.22 लाख को ही नौकरी नसीब हो सकी। प्रति वर्ष औसतन 90,000 नागरिकों को ही केंद्र में नौकरी मिल सकी। राज्यों में रोजगार की स्थिति क्या है, उस पर कोई नियमित डाटा उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार भी पूरा और नियमित डाटा नहीं देती है, लिहाजा मांग उठने लगी है कि मोदी सरकार नौकरियों को लेकर 'श्वेत-पत्र' जारी करे। उसमें सरकारी, निजी और कॉरपोरेट क्षेत्रों को शामिल किया जाए कि किसने, कितनी नौकरियां और किन विभागों में मुहैया कराई हैं।

अकेले लड़ने की जिद पर अड़ीं मायावती के समक्ष बसपा को टूट से बचाने की चुनौती खड़ी है

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब बहुजन समाज पार्टी से सांसद कुंवर दानिश अली की एक तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ने लगी।

बसपा सुप्रीमों मायावती की एकला चलो वाली थ्योरी ने कांग्रेस-समाजवादी पार्टी वाले आईएनडीआईए गठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी हैं, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि बीजेपी के खिलाफ सपा-बसपा को साथ लिए बिना कोई गठबंधन बनता है तो ऐसे गठबंधन की कोई अहमियत नहीं रह जाती है क्योंकि कांग्रेस का तो यूपी में वजूद ही नहीं बचा है। बीजेपी को सपा-बसपा से जरूर थोड़ी-बहुत चुनौती मिलती रही है, लेकिन बसपा का दर्द अलग है। उसका हमेशा से मानना रहा है कि जब भी उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ अन्य किसी दल के साथ गठबंधन करती है तो उसका वोट तो दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बसपा प्रत्यशी को गठबंधन में दूसरे दलों के वोट नहीं मिलते हैं। इसीलिए अपने पुराने अनुभव के आधार पर अबकी से बसपा ने अकेले चलने का निर्णय लिया है, यह बीएसपी का एक राजनैतिक निर्णय हो सकता है, लेकिन इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु बसपा सुप्रीमो मायावती को इसकी चिंता नहीं है, वह तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही एक ही थाली का बैगन बताती हैं। दोनों पर ही दलितों के साथ अत्याचार का आरोप लगाती हैं। मायावती कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हैं। परंतु उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब भी बहुजन समाज पार्टी कमजोर नजर आती है, तब उसमें टूट हो जाती है। अतः इससे भी मायावती को बचकर चलना होगा। यानी उनके सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ पार्टी को जीत की राह पर ले जाना है तो दूसरी ओर उन्हें पार्टी को टूट से भी बचाने की चुनौती होगी।

बसपा की रणनीति अपनी जगह है, मगर इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि आज की बसपा में वह दमखम नहीं रह गया है जो उसमें 2012 से पहले देखने को मिलता था। पिछले कई चुनावों में बसपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। मायावती कभी बड़ी-बड़ी रैलियों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मायावती ने ऐसी कोई रैली नहीं की है जिससे उनकी ताकत का अंदाजा विरोधियों को लग पाए। चुनावी मौसम में एक ओर जहां पार्टियां अपनी तैयारियों और उम्मीदवारो के चयन पर मंथन कर रही हैं, अपने राजनीतिक भविष्य की नैय्या पार लगाने के लिए नेता भी हाथ पांव मार रहे हैं, ऐसे में बसपा आलाकमान को यह समझना होगा कि यदि वह आम चुनाव में थोड़ी भी कमजोर नजर आईं तो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता कमजोर राजनैतिक हालात में दूसरी नाव पर सवार होने में कतई देर नहीं लगाएंगे।

वैसे भी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब बहुजन समाज पार्टी से सांसद कुंवर दानिश अली की एक तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ने लगी। दानिश की इस तस्वीर ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को टेंशन में जरूर डाल दिया होगा, यदि दानिश अपनी पार्टी अध्यक्ष मायावती को बिना बताए नीतीश कुमार से मिले होंगे तो जल्द उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाये तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उधर, दानिश अली ने नीतीश कुमार से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है।

नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर बसपा सांसद ने बताया कि उनके साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों और देश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर चर्चा की। हाल ही में लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में मायावती के नेतृत्व में हुई बैठक में भी दानिश अली कहीं नजर नहीं आये थे। वहीं दावा किया जा रहा है कि सिर्फ दानिश अली ही नहीं बसपा के कई अन्य सांसद भी दूसरे दलों के नेताओं के साथ मिल रहे हैं।

ज्ञातव्य हो कि बहुजन समाज पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मेरठ, अमरोहा, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, गाजीपुर समेत 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि उस अनुपात में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीत पाए थे। राजनैतिक पंडितों के लिए यह चौंकाने वाला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी बसपा सुप्रीमो मायावती 2014 की तरह फिर से अकेले दम पर लड़ने जा रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था। देखा जाये तो 2024 में 2019 के रिजल्ट को बरकरार रखना ही बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि यूपी की 80 की 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। उधर सपा भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को खर्चीले तामझाम और नुमाइशी कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही छोटी-छोटी बैठकों के जरिये गांव गांव में बसपा की पकड़ मजबूत बनाकर सर्वसमाज में जनाधार बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पदाधिकारियों को तन मन धन के साथ जुट जाने के भी निर्देश दिए हैं। मायावती ने गठबंधन को लेकर कहा कि यूपी में गठबंधन करके बसपा को फायदे की बजाए नुकसान ज्यादा हुआ है।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी पार्टी का वोट गठबंधन वाली पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट हमारे उम्मीदवार को दिलाने की ना सही नीयत रखती हैं और ना ही क्षमता। इससे पार्टी के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। मायावती सपा-कांग्रेस गठबंधन को भी आड़े हाथों लेती रहती हैं। वह कहती हैं कि सत्ता और विपक्षी पार्टियां अपना-अपना गठबंधन करके केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोंक रही है, जबकि सत्ता में आने के बाद जनता के लिए किए गए वायदे और आश्वासन खोखले ही साबित हुए हैं। बसपा सुप्रीमो कहती हैं उनकी पार्टी दलित समाज को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है जबकि यह लोग उन्हें तोड़कर कमजोर करने की संकीर्ण राजनीति में ही ज्यादातर व्यस्त रहते हैं।

चिंतन

कहा न, अच्छे दिन तो एक स्लोगन था!

नए-नए केन्द्रीय मंत्री थे। एक पार्टी में मिल गये। प्लेट में पांच-सात गुलाब जामुन रखे बारी-बारी से गटक रहे थे। मैंने भी अपनी प्लेट भरी और उनके पास पहुंच गया। गुलाब जामुन का एक पीस पेट में जमा कर मैंने मंत्री जी से पूछा-'क्यों साब ये अच्छे दिनों की उम्मीद कब तक की जा सकती है।' मेरी बात पर हंसने लगे और 'इससे बढिया अच्छे दिन क्या होंगे? हम लोग एक साथ गुलाब जामुन खा रहे हैं।' मेरे मुंह का गुलाब जामुन बाहर आते-आते बचा, मैंने पूछा- 'सर, यह तो पार्टी है। इसमें तो सभी खा रहे हैं। लेकिन आम आदमी की जद में गुलाब जामुन कब तक आयेगा? मेरा मतलब महंगाई पर लगाम लगाने से है।' वे बोले-'मैं सब समझ रहा हूं। देखिये आलू-प्याज को तो हमने सुरक्षित कर लिया है। चीनी के दाम बढ़ाकर उसे भी लगभग स्थिर कर दिया है। भाई चुनाव में हमने 15 हजार करोड़ खर्च किये हैं। जिनसे लिया है, उनको चुकाना भी तो है। एक बार यह देनदारी खत्म हो जाये, बाद में महंगाई को पूरी तरह काबू में कर लेंगे।' मैंने कहा-'यह तो बड़ा लम्बा प्रोसेस है। तब तक नये चुनाव आ जायेंगे और आप कार्पोरेट से फिर धन ले लेंगे और देनदारी हो जायेगी। इस तरह तो आपका घोषणा-पत्र रद्दी की टोकरी में चला जायेगा।' मंत्री जी बोले- 'देखो भाई यह तो एक प्रोसेस है। अच्छे दिन तो हमारा एक स्लोगन था, जिसे जनता ने सच मान लिया। इसमें हमारी क्या गलती है। चुनाव जीतने के लिए पता नहीं क्या-क्या झूठे-सच्चे वायदे करने पड़ते हैं।' मंत्री जी की बात सुनकर मैंने कहा – 'सर, इससे तो आपका भी हश्र पहले वालों की तरह होगा। जनता आपको पटखनी दे देगी।' 'चुनाव नागनाथ और सांपनाथ वाला खेल है। इसमें विकल्प तो कुछ होता नहीं। इसलिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है।

वैसे भी हमने अच्छे दिनों के लिए जनता से दो टर्म मांगे हैं। हमारे नेताजी बोलने में इतने पटु हैं कि मुझे तो दो दशक तक गुलाब जामुन खाने से कोई रोक नहीं सकता।' मंत्री जी ने कहा। 'यह तो सरासर धोखा है। आप इस तरह जनता की आंखों में धूल कैसे झोंक सकते है?' मैंने कहा तो वे बोले - 'देखो शर्मा, ज्यादा देश की चिंता में अपने आप को दुबले मत होने दो। यह हमारा मामला है। जैसा भी होगा सलटा लेंगे। कांदा सस्ता है, रोटी उसी से खाओ। व्रत के दिन आलू उबाल कर खा लो। अब तुम चाहो कि जनता को दोनों टाइम गुलाब जामुन मिले तो भाई यह हमारे हाथ में नहीं है। महंगाई कम करने के लिए हम लोग कैबिनेट की मीटिंग धड़ाधड़ कर रहे हैं। अब यह मरी सुरसा जैसी, महंगाई का तो हम अकेले कर भी क्या सकते हैं।' मैं बोला-'इसका मतलब तो अच्छे दिन नहीं आयेंगे?' वे बोले, 'मैंने कहा न, अच्छे दिन तो स्लोगन था। उसे सत्य मानना बेवकूफी। वैसे भी अच्छे दिन फील गुड की तरह हैं। महसूस करो तो हर दिन अच्छा है। रहा रात का सवाल, हमने इसके लिए शराब के ठेके बढ़ा दिये हैं। पी लो तो नींद अच्छी आयेगी। अब तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, तो पी. एम. क्या करें।' मैंने कहा-'पी.एम. उनका वादा था, अच्छे दिनों का।' मंत्री जी झल्ला कर बोले-'क्या अच्छे दिनों की रट लगा रखी है। एक बार बता दिया कि अच्छे दिन तो स्लोगन था। बिना मतलब माथा खा गये। हटो दूर में किसी और से मिलता हूं।' यह कहकर मंत्री जी ने गुलाब जामुनों से फिर प्लेट को भरा और वे भीड़ में घुस गये। मुझे काटो तो खून नहीं।

पूरन सरमा

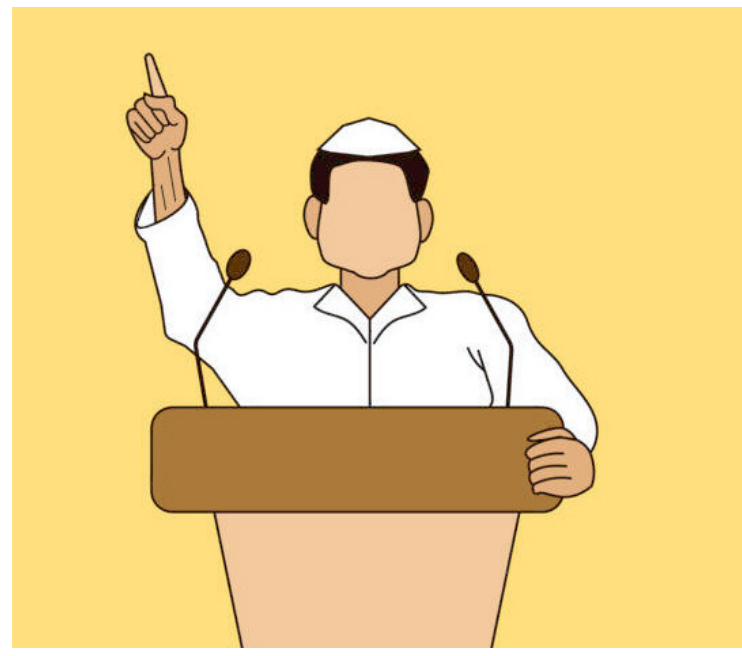

इनसाइड

Reliance Capital के शेयर में लगा अपर सर्किट, जानते हैं क्यों?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज हरे रंग में खुले। बीएसई का सेंसेक्स 230 अंक और एनएसई निफ्टी 79 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे। आज के टॉप गेनर्स शेयरों में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल हैं।

मुंबई: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक आज हरे रंग में कारोबार कर रहे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टेलीकॉम इंडेक्स एकमात्र बढ़त वाला सेक्टोरल इंडेक्स था। आज बीएसई हेल्थकेयर सूचकांक शीर्ष खोने वाला क्षेत्र था। बीएसई सेंसेक्स लगभग 230 अंक या 0.35% ऊपर 65,060 पर और एनएसई निफ्टी-50 इंडेक्स लगभग 79 अंक या 0.41% ऊपर 19,333 पर है। बीएसई पर शुक्रवार को 2,087 शेयरों में तेजी आई, 1,265 शेयरों में गिरावट आई और 163 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

बीएसई पर टॉप गेनर और लूज़र:

टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आज सेंसेक्स में शीर्ष पर रहे, जबकि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड और सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सेंसेक्स में शीर्ष पर रहे।

ब्रॉडर मार्केट में सूचकांकों ने उच्चतर कारोबार किया, बीएसई मिड-कैप सूचकांक क्रमशः 0.69% और बीएसई स्मॉल-कैप सूचकांक 0.82% बढ़ा। शीर्ष मिड-कैप गेनर्स मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैं, जबकि शीर्ष स्मॉल-कैप गेनर्स शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड और अतुल ऑटो लिमिटेड हैं।

01 सितंबर, 2023 तक, बीएसई-लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण लगभग 311 लाख करोड़ रुपये था। इसी के साथ 207 स्टॉक 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर और 11 स्टॉक 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए। अपर सर्किट में बंद पेनी स्टॉक की सूची इस प्रकार है। आगामी सत्रों के लिए इन शेयरों पर कड़ी नजर रख सकते हैं।

एक चुनाव से देश के कितने बचेंगे पैसे? यह हिसाब आपको भी हैरान करेगा

परिवहन विशेष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की पैरवी कर चुके हैं। भारत उन देशों में शामिल है जहां चुनाव कराना बहुत महंगा सौदा है। एक अनुमान के मुताबिक हर वोटर पर आठ डॉलर का खर्च आता है।

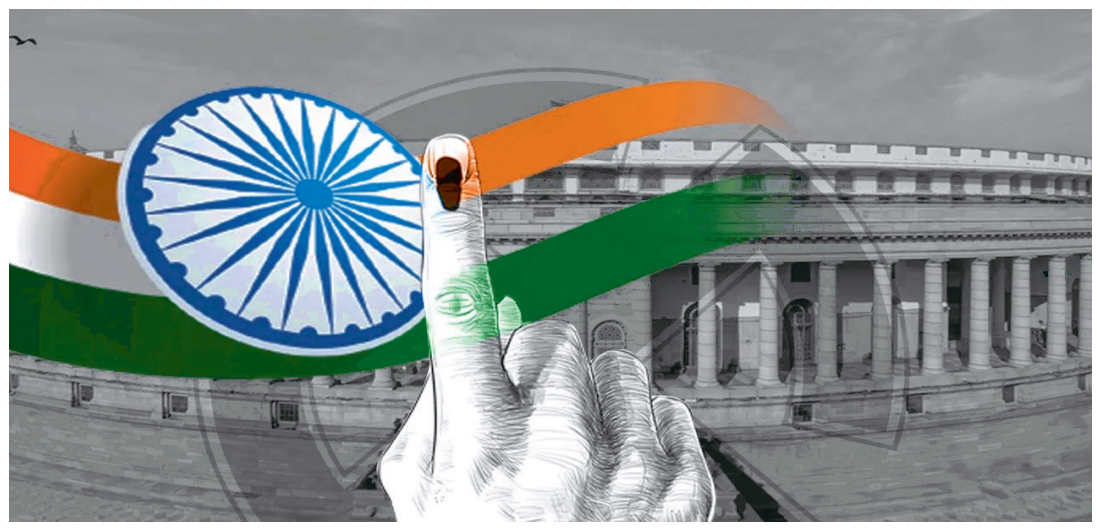

नई दिल्ली: देश में एक देश, एक चुनाव का मुद्दा गरम है। सरकार ने इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है। माना जा रहा है कि यह समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। भारत उन देशों में हैं जहां चुनाव कराना बेहद खर्चीला माना जाता है। वन नेशन, वन इलेक्शन के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यही दी जा रही है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक साल 2019 में हुए आम चुनावों पर 55,000 करोड़ रुपये का खर्च आया था जो 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों से भी ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनावों में हर वोटर पर आठ डॉलर का खर्च आया था जबकि देश में आधी से ज्यादा आबादी रोजाना तीन डॉलर से भी कम पर गुजारा करने को मजबूर है। ऐसे में चुनावों पर भारी-भरकम खर्च को लेकर सवाल उठने जायज हैं।

हर चुनाव के साथ यह खर्च बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 1998 से 2019 के बीच चुनावी खर्च में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। 1998 में यह राशि 9,000 करोड़ रुपये थी जबकि 2019 में 55,000 करोड़ रुपये पहुंच गई। राजनीतिक पार्टियां चुनावों पर जमकर पैसा बहाती हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। साल 2022 में चुनाव आयोग ने पांच राज्यों पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों में हुए खर्च के आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने इन पांच राज्यों में चुनाव प्रचार पर 340 करोड़ रुपये और कांग्रेस ने 190 करोड़ रुपये खर्च किए। जानकारों का कहना है कि ये वे आंकड़े हैं जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग को देते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में इससे कहीं ज्यादा खर्च होता है।

क्या है बाधा

अब सवाल है कि क्या वन नेशन, वन इलेक्शन से इस खर्च पर लगाम लगाई जा सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कई बार वन नेशन, वन इलेक्शन की पैरवी कर चुके हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक अस्थिरता है। साल 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होते थे। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए। कई बार विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं तो कई बार केंद्र सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई।

भर गई सरकार की झोली, जीडीपी के बाद जीएसटी कलेक्शन में भी उछाल

अगस्त में जीएसटी कलेक्शन में 11 परसेंट बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा के मुताबिक अगस्त में जीएसटी कलेक्शन करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे पहले जुलाई में यह 1,65,105 करोड़ रुपये रहा था।

नई दिल्ली: इकॉनमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर आई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) में 11 परसेंट बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा के मुताबिक अगस्त में जीएसटी कलेक्शन करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये रहा। इससे पहले जुलाई में यह 1,65,105 करोड़ रुपये रहा था। मल्होत्रा ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 11 परसेंट बढ़ा है। अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 1,43,612 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था। मल्होत्रा ने कहा कि मोटे तौर पर इसमें सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं। जीएसटी का आंकड़ा शुक्रवार को शाम तक जारी किया जाएगा। मल्होत्रा ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत था। जून तिमाही में जीएसटी रेवेन्यू 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसका मतलब है कि कर-जीडीपी का अनुपात 1.3 से अधिक है।

यह पांचवां मौका है जब जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। रक्षाबंधन के साथ ही देश में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। त्योहारों में लोग बढ़चढ़कर खरीदारी करते हैं। खासकर दिवाली के मौके पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। यानी आने वाले महीनों में जीएसटी कलेक्शन के और बेहतर होने की उम्मीद है। इससे पहले सरकार ने कल यानी 31 अगस्त को जीडीपी का आंकड़े जारी किए थे। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.1 फीसदी रहा था।

दो हजार रुपये का नोट देख लें, कहीं आपके घर पड़ी हो तो यह करें

2,000 रुपये का नोट चलन से बाहर किए जाने का ऐलान हो चुका है। आरबीआई ने इस नोट को बैंक में जमा करने या इसे बदलने की अंतिम तिथि की घोषणा कर दी है। आपके पास इस नोट को बदलने के लिए अभी 30 दिन और बचे हैं।

नई दिल्ली: अगर आपके पास दो हजार रुपये का नोट है तो ये खबर आपके काम की है। सरकार ने दो हजार रुपये का नोट वापस लेने का फैसला किया है। यह फैसला क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत किया गया है। इसे आप या तो खर्च कर सकते हैं या फिर बैंक (Commercial Banks) में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब आपके पास सिर्फ एक ही महीने का वक्त बता है। इस दौरान आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यह सिर्फ कागज का टुकड़ा भर रह जाएगा।

बंद हो गया है सर्कुलेशन

देश में बैंकिंग क्षेत्र के नियामक (Banking Regulator) रिजर्व बैंक (RBI) ने दो हजार रुपये के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 के रुपये के इन नोटों को 30 सितंबर 2023 तक ही बैंक में जमा कराया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। इस तारीख के बाद आप न तो इस नोट को बैंक में जमा कर पाएंगे और न ही इसे खर्च कर पाएंगे।

एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं

आरबीआई के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक की सीमा तक बिना कोई फॉर्म या मांग पर्ची भरे नोट को बदल सकता है। इसके अलावा एक्सचेंज के समय लोगों को किसी भी तरह की पहचान प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने जब इन नोटों को चलन से बाहर करने की योजना की घोषणा की थी तो लोगों को नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया था।

नोट बदलने के क्या हैं नियम

आरबीआई ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि दो हजार रुपये के नोट को सिर्फ सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। नोट पूरी तरह से वैध हैं। आप इन नोटों का इस्तेमाल खरीदारी में, लेनदेन में जहां चाहे वहां कर सकते हैं। इसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप इस बात को गांठ बांध लें कि जिनके पास भी 2,000 रुपये का नोट है, वो बैंक जाकर इसे बदलवा सकते हैं। नोट बदलवाने का कोई पैसा नहीं लगेगा।

कब बाजार में आए थे 2,000 के नोट

करीब साढ़े छह साल पहले हुई इस नोटबंदी के बाद सरकार ने 2,000 रुपये के नए नोट शुरू किए थे। रिजर्व बैंक ने आईबीआई एक्ट की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2 हज़ार रुपये के नए नोट जारी किए थे। उसी समय इस मूल्य वर्ग के अधिकतर नोट छापे गए थे। उस समय भी इस नोट को लाने पर सवाल उठा था। तब बताया गया था कि ऐसा नोटबंदी के बाद पैदा हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। जब बाजार में अन्य नोट पर्याप्त मात्रा में आ गए, उसके बाद साल 2018-19 में दो हजार रुपये के नोट छापने बंद कर दिए गए थे। आरबीआई ने बताया था कि दो हजार रुपये के 89 फीसदी नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे।

नोएडा एयरपोर्ट के पास सस्ते में लेना है प्लॉट तो आज है अंतिम दिन, यहां जानिए पूरी डिटेल

जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदने का आज आखिरी मौका है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक योजना के जरिए जेवर एयरपोर्ट के पास 1,184 प्लॉट बेच रही है। इसके लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है।

नई दिल्ली: दिल्ली के करीब नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट का काम जोरशोर से चल रहा है। इसके साथ ही इसके आसपास प्रॉपर्टी की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। ऐसे में आपके पास सस्ते में प्लॉट पाने का आज आखिरी मौका है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) जेवर एयरपोर्ट के करीब 1,181 प्लॉट बेच रही है। इसमें इंडिपेंडेंट हाउस के लिए प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। बुधवार शाम तक पोर्टल पर 1.73 लाख लोग इसके लिए आवेदन कर चुके थे। इस योजना को 8 अगस्त को लॉन्च किया गया था और आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी एक सितंबर 2023 है। 18 अक्टूबर 2023 को ड्रॉ के जरिए आवेदन खोले जाएंगे।

बुधवार तक के आंकड़ों के मुताबिक 1.23 लाख ऑनलाइन फॉर्म खरीदे गए हैं और 1.1 लाख आवेदन जमा किए गए हैं। वहीं 78,290 आवेदकों ने 10% बयाना राशि का भुगतान भी किया है। इस योजना में मिल रहे आवासीय भूखंड सात अलग-अलग आकार के हैं। इस योजना में 120 वर्गमीटर से लेकर 2000 वर्गमीटर तक के प्लॉट हैं। कुल 1181 प्लॉट्स में से 919 प्लॉट्स जनरल कैटिगरी के लिए है। बाकी किसानों तथा अन्य कैटिगरी के लिए रिजर्व हैं। यमुना अथॉरिटी के ये प्लॉट्स यमुना सिटी के सेक्टर-16, 17 और 20 में हैं।

कितनी है कीमत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस जगह पर प्लॉट्स के रेट 24 हजार 600 रुपये प्रति वर्गमीटर रखा गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहीं से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस योजना में प्लॉट खरीदने के लिए आपको आवेदन के समय प्लॉट की कीमत का 10 फीसदी पैसा जमा करना होगा। अगर आप 120 मीटर का प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको करीब 2 लाख 95 हजार 200 रुपये जमा करने होंगे। इसी तरह से बड़े प्लॉट के लिए ज्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे।

जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य इन दिनों फुल स्विंग में चल रहा है। एक बार जब यह एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो आसपास के जमीन के भाव आसमान में पहुंचने की बात की जा रही है। इसी वजह से यहां पर प्लॉट खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते इस जगह की कीमत आने वाले समय में काफी बढ़ सकती है। हाल के दिनों में जेवर एयरपोर्ट के करीब प्रॉपर्टी के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास विकास के कई काम हो रहे हैं। YEIDA देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी काम कर रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी से इतना चिढ़ता क्यों हैं यह अमेरिकी बिजनसमैन, जान लीजिए पूरी कुंडली

अमेरिकी बिजनसमैन जॉर्ज सोरोस एक बार फिर चर्चा में हैं। इनके सपोर्ट वाली मीडिया संस्था OCCRP ने गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट छापी है। सोरोस ने दुनिया के कई मीडिया संगठनों में निवेश किया है।

नई दिल्ली: अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस (George Soros) एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके सपोर्ट वाली नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था OCCRP ने भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी (Gautam Adani) और अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) पर निशाना साधा है। उसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया। OCCRP ने एक अन्य रिपोर्ट में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर देश के पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने के लिए गुपचुप तरीके से लॉबिंग करने का आरोप लगाया है। 92 साल के सोरोस की पहचान एक ऐसे शख्स की रही है जो दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए अपना एजेंडा चलाता है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की नीतियों का भी धुर आचोलक माना जाता है।

जॉर्ज सोरोस अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक हैं। लेकिन उनकी छवि काफी विवादित रही है। वह सटोरिए, निवेशक और कारोबारी हैं लेकिन खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहता है। आरोप है कि उन्होंने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी-भरकम फंडिंग की है। यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगा दी गई है। आरोप है कि सोरोस दुनिया कई देशों में कारोबार और समाजसेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देते हैं।

मोदी के धुर आलोचक

सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के धुर आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सोरोस ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संसोधन कानून (CAA) का भी खुलकर विरोध किया था। जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी में अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी तो सोरोस काफी मुखर हो गए थे। उन्होंने कहा कि अडानी का पीएम मोदी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक-दूसरे के लिए जरूरी हो गए हैं। सोरोस ने कहा था, 'इस मुद्दे पर मोदी चुप हैं लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार पर मोदी की पकड़ ढीली होगी और संस्थागत सुधारों के दरवाजे खुलेंगे।'

सोरोस का जन्म साल 1930 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ। साल 1947 में वह अपने परिवार के साथ लंदन आ गए। परिवार को पालन-पोषण करने के लिए उन्होंने कुली और वेटर के तौर पर काम किया। इसी से पैसा जुटाकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ाई की। साल 1956 में वह लंदन से अमेरिका चले गए और वहां फाइनेंस तथा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम किया। साल 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट के नाम से कंपनी बनाई। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और अगले 6 साल में करोड़पति बन गए।

सोरोस पर आरोप

जॉर्ज सोरोस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर साल 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह कर खुद की जेब भरने का आरोप लगा। ब्रिटेन को तब ब्लैक वेंजडे का सामना करना पड़ा था जिसमें सोरोस ने एक अरब डॉलर की कमाई की थी। अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की मदद से वह करीब 100 देशों में सक्रिय हैं। आरोप है कि जॉर्ज बुश को हराने के लिए उन्होंने 125 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इतना ही नहीं उन्होंने मीडिया कंपनी फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए 10 लाख डॉलर लगा दिए थे। इसी तरह ब्रेक्जिट के खिलाफ अभियान चलाने में चार लाख पाउंड खर्च कर दिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को ठग कहा था।

सोरोस ने 2020 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (WEF) में मोदी, ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह कहा था। उनका कहना था कि ये सभी नेता अपने-अपने देशों में लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही का बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ट्रंप को उन्होंने ठग और आत्ममुग्ध जबकि पुतिन को तानाशाह शासक कहा था। सोरोस ने कहा था कि जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा तोड़कर सत्ता की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है।

कैसे कमाया पैसा

सोरोस पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अनैतिक तरीकों से पैसा बनाया है। वर्ष 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक और अनधिकृत व्यापार का दोषी पाया था। इसके लिए फ्रेंच कोर्ट ने सोरोस पर 23 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था। जब उन्होंने फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी तो उसने भी सोरोस का जुर्माना बरकरार रखा। इसी तरह उन पर अमेरिका में भी बेसबॉल में पैसा लगाकर अनैतिक तरीके से पैसे बनाने का आरोप लगा। इटली की फुटबॉल टीम एएस रोमा को लेकर भी सोरोस विवादों में आए। सोरोस ने अपनी मां को आत्महत्या करने में मदद की थी। इस बात का खुलासा उन्होंने ही साल 1994 में किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोरोस ने दुनियाभर में कई मीडिया कंपनियों में निवेश किया है। अमेरिका का मीडिया वॉचडॉग मीडिया रिसर्च सेंटर की मानें तो सोरोस ने 180 से अधिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर किया है। अमेरिका में उनका 30 से अधिक मीडिया आउटलेट्स में उनका डायरेक्ट निवेश है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, एपी, सीएनएन और एबीसी शामिल हैं। अडानी और अग्रवाल पर आरोप लगाने वाली संस्था OCCRP के सपोर्टर्स में ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस शामिल हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को सोरोस को सपोर्ट हासिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोरोस ने फरवरी 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट में तीन परसेंट हिस्सेदारी 10 करोड़ डॉलर में खरीदी थी। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2007 में सनटीवी नेटवर्क में 0.5 फीसदी हिस्सेदारी ली थी।

घरेलू के बाद कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ सस्ता, जानिए कितनी रह गई है अब कीमत

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बाद सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी कमी की है। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 158 रुपये की कटौती की गई है। इसके बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1522 रुपये रह गई है।

नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बाद सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylinder) की कीमत में भी कमी की है। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 158 रुपये की कटौती की गई है। इसके बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1522 रुपये रह गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक नए रेट आज से लागू हो गए हैं। कोलकाता में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब 1636 रुपये, मुंबई में 1482 रुपये और चेन्नई में 1695 रुपये रह गई है। पिछले महीने की पहली तारीख को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती की कई थी। उससे पहले जुलाई में इसकी कीमत में सात रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले सरकार ने रक्षा बंधन के मौके पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी 200 रुपये की कटौती की घोषणा की थी। इससे दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये से घटकर 903 रुपये रह गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर अब 703 रुपये का हो गया है। सरकार ने साथ ही घरेलू एलपीजी पर इम्पोर्ट ड्यूटी और एग्री तथा इन्फ्रा सेस भी 15 परसेंट से घटाकर जीरो कर दिया है। निजी कंपनियों के एलपीजी आयात करने पर 15 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी और 15 परसेंट एग्री तथा इन्फ्रा सेस लगता था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि नई दरें आज यानी एक सितंबर, 2023 से लागू हो गई हैं। इससे पहले एक जुलाई को सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पांच परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट कर दी थी। साथ ही एलपीजी सिलेंडर्स पर 15 परसेंट एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगा दिया था। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों को इससे अलग रखा गया था।

नेशनल स्पोर्ट्स के अवसर पर मास्टर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स क्लब अमृतसर, के सरपस्त दिल्ली मोटरसाइकिल हाउस के सुरजीत सिंह

अमृतसर (साहिल बेरी) क्लब के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मास्टर्स एथलीट को सम्मानित किया और इस अवसर पर लड़कों की 1600 मीटर दौड़ और लड़कियों की 800 मीटर दौड़ आयोजित की गई और जिन खिलाड़ियों ने पुरस्कार जीते पदों को ट्रॉफी और किट से सम्मानित किया गया, यह कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद की स्मृति में आयोजित किया गया था, इस अवसर पर क्लब के सरपस्त सुरजीत सिंह दिल्ली मोटर साइकिल हाउस, एडवोकेट सुधीर सियालकोटी, अध्यक्ष डॉ. वंदना, अवतार सिंह अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पीपीसी सचिव, अनुभव वरमानी , बहादुर सिंह बल, नगीन सिंह, राजीव गिल, रणजीत सिंह, गुरविंदर सिंह आरओ, कोमल वडाली, सुखदेव सिंह, जागीर सिंह, कोच राजिंदर छीना।

अदालत ने पंजाब सरकार के फैसले को खारिज कर ग्राम पंचायतों की बहाली कर दर्ज की लोकतंत्र की जीत: विशाल मेहता

अमृतसर (साहिल बेरी) : मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा संविधान का उल्लंघन कर पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों को भंग करके उनके अधिकार छीनने को लेकर यह मामला माननीय अदालत में जा पहुँचा, जिसको लेकर आज माननीय अदालत ने पंजाब सरकार के फैसले को खारिज करते हुए सभी ग्राम पंचायतों को फिर से बहाल कर दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब के प्रदेश मीडिया इंचार्ज विशाल मेहता ने माननीय अदालत द्वारा सुनाए फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया।

विशाल मेहता ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने राज्य भर की पंचायतों के पंच-सरपंच साहिबान और सभी लोगों को बधाई देते हुए माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की भी जीत हुई है और यह सभी पंजाबियों के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने पंचायत संस्थाओं के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पंचायतों को भंग करने का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक था।

विशाल मेहता ने कहा कि पंजाब की आम आदमी सरकार द्वारा 10/08/2023 को पंजाब की सभी ग्राम पंचायतें, ब्लॉक समितियां और जिला परिषदें 10/08/2023 को भंग कर दी गई थीं। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मानयोग अदालत द्वारा आज पंजाब सरकार के फैसले को रद्द करते हुए आज सभी ग्राम पंचायतें बहाल कर दी गई हैं। विशाल मेहता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान जी बाबा साहेब जी की फोटो लगाने से उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। कृप्या उनके लिखित संविधान का पालन करें और सब कुछ संविधान के अनुसार करें ताकि आपके निर्णय अमान्य ना हों।

औरतों को राखी का तोहफ़ा; मुख्यमंत्री ने 5714 आंगनवाड़ी वर्करों को नियुक्ति पत्र सौंपे

सरकार ने राज्य के 35,000 से अधिक नौजवानों को नौकरियाँ दीं

साहिल बेरी

अमृतसर। पंजाब में औरतों को राखी का तोहफ़ा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती के लिए 5714 आंगनवाड़ी वर्करों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यहाँ गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस में करवाए गए राज्य स्तरीय समागम के दौरान संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के नौजवानों की असीम ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाने के लिए पंजाब सरकार ने 35,000 से अधिक नौजवानों को नौकरियाँ दी हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा किया गया है और नौजवानों को नौकरियाँ पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सभी कर्मचारियों और वर्करों का कल्याण यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को दी गईं रिकॉर्ड संख्या में नौकरियाँ उनको राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में हिस्सेदार बना रही हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि वह छोटी उम्र में बच्चों के भविष्य को बनाने और उनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं।

मुख्यमंत्री ने जनसभा को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी वर्करों के कल्याण के लिए और अहम पहलें करेगी, जिससे यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि सेवाओं को सुचारू ढंग से निभाने के दौरान उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। राखी के त्योहार के अवसर पर आंगनवाड़ी वर्करों के साथ सांझ की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि अब बेटियाँ हर क्षेत्र में लडक़ों को पछाड़ रही हैं और माँ-बाप को बेटी का पालन-पोषण करके गर्व महसूस होता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि लड़कियों ने जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी काबिलीयत का सबूत दिया है और हम सभी को समाज की बेहतरी के लिए बेटियों को अपने सपने साकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अफ़सोस प्रकट किया कि पहले बेटियों को 'कुडियाँ-चिडियाँ' कहा जाता था, परन्तु अब अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगन से लड़कियों ने साबित कर दिया है कि वह वास्तव में 'शेरनियाँ' हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह लड़कियों के लिए शिक्षा और रोजग़ार के नये रास्ते खोलकर उनको अधिक अधिकार दे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनका पक्का विश्वास है कि अगर लड़कियों को अवसर दिया जाये तो वह जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफलता की नयी इबारत लिख सकती हैं।

अपने भ्रष्ट साथियों की हिमायत में कलम छोड़ हड़ताल करने की योजना बना रहे सरकारी कर्मचारियों को सख़्त कार्यवाही की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का ऐसा ग़ैर-

ज़िम्मेदाराना व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और सरकारी कर्मचारियों की हड़तालों के कारण लोगों को होने वाली परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों की जायज माँगों को हल करने के लिए हमेशा तत्पर है, परन्तु वह उन लोगों की हिमायत में की जाने वाली ब्लैकमेलिंग को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिनको लोगों की लूट करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने अनिवार्य सेवाओं एक्ट को लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन कर्मचारियों द्वारा छुट्टी पर जाने की सूरत में उनके विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जा सके।

मुख्यमंत्री ने भावुक लहजे से कहा कि उनकी माँ संगरूर में अपने पैतृक गाँव में रहना पसंद करती हैं और उनको अपनी माँ को मिले 40 दिन से अधिक हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह पंजाब की निष्ठापूर्वक सेवा करने के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी क्योंकि पंजाब की सभी बुज़ुर्ग माताओं का आशीर्वाद उनके साथ है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब भी उनके माता जी गाँवों का दौरा करने के समय पर बुज़ुर्गों को मिलते और उनके पैर छूते हुए देखते हैं तो उनको गर्व महसूस होता है कि उनका बेटा राज्य के कल्याण के लिए अथक मेहनत कर रहा है और पंजाब की खो चुकी शान को बहाल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।

पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बेलगाम होने पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के साथ कतई लिहाज़ न बरतने की नीति अपनाई है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने आम आदमी की बेटियों-बेटों को अधिक अधिकार देकर राज्य की राजनीति में एक बेमिसाल बदलाव लाए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिन लोगों ने अपने शासनकाल के दौरान अपने आप को महलों में कैद कर लिया था, उनको लोगों ने राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया है और अब एक लोक-समर्थकीय सरकार मिशनरी भावना से लोगों की सेवा कर रही है। इस मौके पर एक आंगनवाड़ी वर्कर ने स्टेज पर मुख्यमंत्री को राखी भी बाँधी।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर, हरभजन सिंह ई.टी.ओ और कुलदीप सिंह धालीवाल भी उपस्थित थे।

संसद के विशेष सत्र में लोकसभा भंग ? : सूत्र

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने से राजनीतिक भूकंप आ गया है। सूत्रों के मुताबिक , पांच दिन के विशेष सत्र में लोकसभा भंग करने पर अटकले गर्म है। दिसंबर में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव पर हो सकता फैंसला। उधर इन अटकलों के बीच चुनाव आयोग का ब्यान भी आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया है कि अगर समय से पहले चुनाव हुए तो आयोग एक महीने के भीतर चुनाव कराने की तैयारी कर लेगा। उधर लोकसभा भंग की अटकल के बीच मीडिया के सवालों पर कांग्रेस के राशीद अल्वी ने कहा कि मोदी जी इंडिया की एकता से घबरा गए हैं। वह विपक्षी दलों की अधपकी तैयारी का फायदा उठाना चाहते हैं। बहरहाल संसद के सत्र में यूसीसी को लाने का मसौदा तैयार है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर जल्दबाजी में बीजेपी लोकसभा भंग का कदम उठाती है तो यह बीजेपी के लिए आत्मघाती होगा। मीडिया में चल रही इन खबरों से राजनीतिक महौल खासा गर्मा गया है। अब देखना ये है कि पीएम मोदी का ऐसा फैंसला क्या गुल खिलाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग किसी भी घोषणा को लेकर तैयार है। सरकार का यह आखिरी सत्र माना जा रहा है।

चरण स्पर्श फाउंडेशन और गुरुग्राम पुलिस ने सरहौल के सरकारी स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया

पवन कुमार जुनेजा

हरियाणा। शुक्रवार 01 सितम्बर2023 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरहौल गुरूग्राम में सडक़ सुरक्षा डिजिटल जागरूकता अभियान का आयोजन चरण स्पर्श फाउंडेशन ने गुरूग्राम पुलिस के साथ मिलकर किया गया। आयोजन मे चरण स्पर्श की संस्थापक माया ठाकुर के साथ यातायात प्रभारी पश्चिम उप निरीक्षक कंवर भान और विद्यालय के प्राचार्य श्री गोपाल प्रसाद, एएसआई राजेश कुमार और उनकी टीम मौजूद रहे।

छात्रों को सम्भोदित करते हुए चरण स्पर्श फाउंडेशन की संस्थापक माया ठाकुर ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021' रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की 4,12,432 घटनाएं हुईं, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान गई और 3,84,448 लोग घायल हुए। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी की बात को आगे रखते हुए कहा कि 2025 के अंत से पहले सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा संयुक्त प्रयास आवश्यक होंगे।

दरअसल, सड़क सुरक्षा दुनिया भर में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझों में से एक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ, सड़क सुरक्षा देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क दुर्घटना से संबंधित चोटें मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए गंभीर सामाजिक-आर्थिक लागत है ।

चरण स्पर्श फाउंडेशन टीम ने सवाल जवाब के जरिए छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। इस ड्राइव का उद्देश्य छात्रों (मोटर चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों) को जागरूक बनाना है, सडक़ पर रहते हुए, यातायात उल्लंघन को कम करने, और वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, निर्धारित गति सीमा के भीतर सुरक्षित रूप से ड्राइव करने , लेन अनुशासन का पालन करने, ड्राइविंग करते समय सिग्नल देना और मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना, वैध लाइसेंस के साथ ड्राइव करना, आदि सब यातायात के नियमो का पालन करने के लिए प्रेरित करना है. छात्र प्रतिभागियों को डीपी जैन ट्रस्ट द्वारा विशेष पुरुस्कार वितरित किए गए

लिव-इन-पार्टनर विवाह की संस्था को नष्ट करने के

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। लिव-इन- पार्टनर से बलात्कार के आरोपी एक शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में विवाह की संस्था को नष्ट करने के लिए सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से एक डिजाइन काम कर रहा है। इनमें फिल्में और टीवी धारावाहिकों का खासा योगदान है। हाइकोर्ट ने टीवी धारावाहिकों और वेब सीरीज के कंटेंट पर टिप्पणी करते कहा कि हर सीजन में साथी बदलने की अवधारणा को 'स्थिर और स्वस्थ 'समाज की पहचान नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा विवाह संस्था किसी व्यक्ति को जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। लिव-इन-रिलेशनशिप से उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने लिव-इन-रिलेशनशिप को इस देश में विवाह की संस्था के अप्रचलित होने के बाद ही सामान्य माना जाएगा। जैसा कि कई तथाकथित विकसित देशो में होता है, जहां विवाह की संस्था की रक्षा करना उनके लिए एक बडी समस्या बन गई है। हम भविष्य में अपने लिए एक बडी समस्या खडी करने की दिशा में आगे बड रहे हैं। शादी शुदा रिश्ते में पार्टनर से बेवफाई और स्वतंत्र लिव-इन-रिलेशनशिप को एक प्रगतिशील समाज के लक्षण के रूप में दिखाया जा रहा है। युवा ऐसे दर्शन की ओर आकर्षित हो जाते हैं।क्योंकि वह दीर्धकालिक परिणामों से अनजान होते हैं।न्यायालय का यह भी मानना है कि जिस व्यक्ति के पारिवारिक रिश्ते मधुर नहीं है, वह राष्ट्र की प्रगति में योगदान नहीं दे सकता। न्यायमूर्ति सिध्दार्थ ने यह भी कहा कि एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाने में जाने से कोई संतुष्टिदायक अस्तित्व नहीं मिलता है। और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों को बहुत सरी समस्याओ का सामना सामना करना पडता है। पीठ ने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चौं के माता- पिता जब अलग हो जाते हैं,तब वे समाज पर बोझ बन जाते हैं। और गलत संगत में पड जाते हैं। और नागरिकों की राष्ट्रीय हानि होती है। ऐसे रिलेशनशिप में पैदा हुई कन्या शिशु के मामले में अन्य दुष्प्रभाव भी होते हैं।जिन्हें बताना संभव नहीं है। अदालतों को रोजाना ऐसे मामले देखने को मिलते है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार हैं। **Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**